fo"k; lwph

उप-चुनाव परिणाम

गुजरात................................ 4
दिल्ली.................................. 5
उत्तराखंड............................ 6

विधानसभा चुनाव रिपोर्ट

महाराष्ट्र............................... 13
अरुणाचल प्रदेश.................. 15

लेख

जरूरी है एकीकृत खाद्यान्न बजट
– विष्णुदत्त नागर......... 16
लोकतंत्र को थरुरों से बचाना जरूरी
– विष्णु गुप्त................ 18
दीनदयालजी के संग
– विजय कुमार गुप्त... 30

साक्षात्कार

श्री शांताकुमार....................... 21

मोर्चा/प्रकोष्ठ

व्यापार प्रकोष्ठ रा.का. बैठक.. 23
भाजयुमो कार्यशाला................ 24

प्रदेशों से

उत्तराखण्ड.......................... 7
कर्नाटक............................. 14
मध्यप्रदेश............................ 25
झारखण्ड, दिल्ली................ 26
छत्तीसगढ़............................ 28

सम्पादक

प्रभात झा, सांसद

सम्पादक मंडल

सत्यपाल

के. के. शर्मा

संजीव कुमार सिन्हा

पृष्ठ संयोजन

धर्मेन्द्र कौशल

सम्पर्क

Mk- eqdthZ Lefr U;kl

ihih&66] lqcze.;e Hkkjrh ekxZ

ubZ fnYyh&110003

Qksu ua- +91¼11½&23381428

QSDl ¼ +91¼11½&23387887

lnL;rk gsrq ¼ +91¼11½&23005700

सदस्यता शुल्क

okf"kZd 100#- | f=okf"kZd 250#-

e-mail address

kamalsandesh@yahoo.co.in

प्रकाशक एवं मुद्रक : डा. नन्दकिशोर गर्ग द्वारा डा. मुकर्जी स्मृति न्यास, के लिए एक्सेलप्रिंट, सी–36, एफ.एफ. कॉम्पलेक्स, झण्डेवालान, नई दिल्ली–55 से मुद्रित करा के, डा. मुकर्जी स्मृति न्यास, पी.पी–66, सुब्रमण्यम भारती मार्ग, नई दिल्ली–110003 से प्रकाशित किया गया। : सम्पादक – प्रभात झा

lEikndh;

कमल संदेश

अर्थ, काम यदि धर्म के अनुसार न हो तो उनका त्याग करना चाहिए।

-मनुस्मृति 4&176

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

समाज को खड़ा होना होगा

'राजनीति को शुचित होना होगा। शुचितापूर्ण सादगी और सहजता से जीने वाले राजनीतिज्ञ–जीवन की चिंता समाज को करनी होगी। समय रहते ऐसा नहीं हुआ तो अविश्वास और नैराश्यता की खाई राजनैतिक क्षेत्र में और गहरी होगी। समाज को अपना अंकुश बढ़ाना होगा। समाज भी यह दायित्व तब निभा सकता है, जब वो सामाजिक और रचनात्मक कार्यों से जुड़ी जिंदगियों के लिए निःस्वार्थ खड़ा होगा। समाज की निष्क्रियता अनेक अपराधों को जन्म देती है। देश और समाज–जीवन, राजनीति और राजनीतिज्ञों का गिरने का मुख्य कारण समाज की सहनीय चुप्पी है। जो समाज सब कुछ होते देखता है, इस समाज में वह सब कुछ घटता है, जो नहीं घटना चाहिए। 'समाज' पर नहीं बल्कि राजनीति और राजनीतिज्ञों पर समाज को भारी होना होगा। नागरिकशास्त्र से नागरिकबोध को निकालकर समाज जीवन में जन–जागरण का स्वप्न देना होगा। पहरेदार जब सोने लगेंगे तो उस स्थान पर चोरों के पौ–बारह होने की कहावत को घटित होने से कौन रोक सकता है।

महापुरूषों के बोध–वाक्यों में कहा जाता रहा है जहां नागरिकबोध नहीं वहां देशबोध की कल्पना करना स्वयं के साथ मजाक करना है। अतः विचार तो करना ही होगा कि देश में नागरिकबोध के लिए जनजागरण अभियान चले।

आखिर, आजादी के लिए हमने सब कुछ न्यौछावर करने का भाव रखा था, तो आजाद हुए। वहीं हमने 'आजादी अक्षुण्ण और मजबूत बनती रहे' की दृष्टि से हमने सब कुछ राजनेताओं पर छोड़ दिया। इसमें कोई दो मत नहीं नागरिकों से अधिक दायित्व उन महानुभावों का है, जिन्होंने स्वयं को सामाजिक और राजनैतिक क्षेत्रों में झोंका है, पर क्या इतने मात्र से नागरिक अपने नागरिक दायित्वों से बच सकते है? कदापि नहीं।

'आचरण और व्यवहार' में यदि सामाजिकता नहीं है तो जनता अब उन नेताओं के द्वार नहीं जाने वाली जो कदाचरण और अव्यावहारिकाता का जीवन जीते हैं। जनता उनके द्वारा भी नहीं जाने वाली जो कथनी और करनी में अंतर रखते हैं। जनता उनके द्वारा भी नहीं जाने वाली जो समाज और नागरिकों का सम्मान नहीं करते है। 'लोकतंत्र' 60 वर्षों बाद पूरी तरह परिपक्व होती जा रही है। अब कोई चाहे भी तो 'लोकतंत्र' को 'एकतंत्र' में नहीं बदल सकता। यही कारण है कि जनता में जनप्रतिनिधियों को चुनने के अधिकार के साथ उन्हें वापिस बुलाने के लिए भी मतदान और अन्य तरीकों पर विचार करने की मांग उठने लगी है।

आज जनता की जागरूकता और उसकी सक्रियता समाज–जीवन की महती आवश्यकता है। समाज आज भी उन्हें पूजता है जो पवित्र हैं। एक संत ने इससे आगे कहा कि धर्म का बढ़ना उतना ही आवश्यक है जितना पाप का कम होना। धर्म भी बढ़ता रहे और पाप भी तो शायद समाज के साथ न्याय नहीं होगा। अतः यह आवश्यक है कि राजनीति को शुचित करने के लिए समाज स्वयं आगे आए। समाज आदर्श को सहारा और शाबाशी दे और दोषियों को न केवल नकारे बल्कि उन्हें दंडित करने की दिशा में भी कदम बढ़ाए। ■
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

उपचुनाव परिणामों से भाजपा में नया उत्साह

गुजरात में तमाम दुष्प्रचार के बावजूद कांग्रेस से छीनीं 5 सीटें

उत्तराखण्ड और मध्यप्रदेश में भी जीत का परचम

दिल्ली में कांग्रेस की शर्मनाक हार

देशभर के राज्यों में हुए विधानसभा उपचुनावों के परिणामों ने भारतीय जनता पार्टी में एक नई जान फूंक दी है।

सबसे ज्यादा उत्साहवर्धक चुनाव परिणाम गुजरात से आए हैं। उसी गुजरात से जो हमेशा छदम् सेकुलरों के निशाने पर रहता है। उसी गुजरात से जहां के मुख्यमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी को वोट बैंक के सौदागर खलनायक बताते हैं। पर गुजरात की जनता ने एक बार पुनः सिद्ध कर दिया कि वह दुष्प्रचार की आंधी में उड़कर गुजराती अस्मिता से खिलवाड़ करने वालों को माफ नहीं करेगी, और गुजरात की पहचान बन चुके नरेन्द्र मोदी ही उनके नायक हैं। इस बार विधानसभा चुनावों के दौरान कांग्रेस ने फिर गड़े मुर्दे उखाड़े, आतंकवादियों के साथ मारी गई उनकी साथी इशरत जहां को बेकसूर साबित करने वाली रपट प्रकाशित कराई गई, सोहराबुद्दीन का नाम उछाला, पर 10 सितम्बर को 7 विधानसभा क्षेत्रों में हुए मतदान में गुजरात की जनता ने इसका जवाब दे दिया। खास बात यह थी कि इन सात स्थानों में से 6 स्थान कांग्रेस के सदस्यों द्वारा त्यागपत्र दिए जाने के कारण खाली हुए थे और मात्र 1 स्थान भाजपा के सदस्य द्वारा रिक्त किया गया था। पर 14 सितम्बर को जैसे–जैसे

गुजरात

भाजपा में जश्न कांग्रेस में हताशा

विधानसभा उपचुनाव में भारी सफलता से उत्साहित भाजपा कार्यकर्ताओं ने गुजरात में जश्न मनाया। वहीं अपेक्षा के विपरीत आए परिणामों से कांग्रेसी कार्यकर्ताओं में हताशा छा गई।

राज्य में सात विधानसभा चुनावों की सुबह से शुरू हुई मतगणना की शुरूआत से ही अधिकांश सीटों पर भाजपा प्रत्याशियों की बढ़त के रूझान देख पार्टी कार्यकर्ताओं का उत्साह बढ़ने लगा। सुबह करीब नौ बजे तक भाजपा प्रत्याशियों की विजय व तीन अन्य सीटों में पार्टी प्रत्याशियों की भारी बढ़त के आंकड़े बाहर आने के साथ ही सम्बन्धित क्षेत्रों के मतगणना केन्द्रों के बाहर केसरिया ध्वज लहराने लगे, जबकि कांग्रेसी कार्यकर्ताओं में हताशा छाने लगी।

भाजपा प्रत्याशियों को मिल रही भारी बढ़त व जीत की खुशियां मनाने के लिए सुबह 11 बजे से भाजपा कार्यकर्ता पार्टी के प्रदेश कार्यालय जे.पी. चौक खानपुर में एकत्र होने लगे। अपरान्ह साढ़े बारह बजे के दौरान कार्यालय परिसर में उपस्थित पदाधिकारी–कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे को मिठाई खिलाकर खुशियां मनाई। ढोल नगारों के साथ उमड़े कार्यकर्ताओं ने कार्यालय परिसर के बाहर जमकर पटाखे फोड़ कर जश्न मनाया।

वन्देमातरम् का जयघोष व भारत माता की जय.. के नारे लगाते हुए भाजपा कार्यकर्ता हाथों में पार्टी का झण्डा लेकर नाचे–झूमे व एक दूसरे को पार्टी को मिली सफलता की शुभकामनाएं दीं। वहीं दूसरी ओर चुनाव परिणामों के साथ ही कांग्रेसी कार्यकर्ताओं में हताशा बढ़ती चली गई। इससे प्रदेश कांग्रेस कार्यालय राजीव गांधीभवन बिल्कुल सूना पड़ा रहा। हालांकि कार्यालय के बाहर लहराते कांग्रेसी झण्डे सूनेपन को कुछ कम करने में भूमिका निभा रहे थे।

उपचुनाव में भाजपा को मिली भारी सफलता का समाचार मिलते ही मुख्य मंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने तत्काल मतदाताओं का आभार जताने का निर्णय कर लिया। भाजपा के महासचिव जयंती बारोट ने पार्टी कार्यालय पर दोपहर को मनाए जा रहे जश्न के दौरान घोषणा करते हुए कहा कि लोगों ने राज्य सरकार के विकास कार्यों की कद्र करके भाजपा को सफलता दिलाई। इसके प्रत्युत्तर में श्री मोदी ने सबसे पहले दहेगाम क्षेत्र के मतदाताओं का आभार जताया। फिर जसदण व चोटीला के बाद उपचुनाव वाले अन्य क्षेत्रों में जाकर मतदाताओं का आभार जताया। गौरतलब है कि वर्ष1975 से 1998 तक अधिकांशतः जनसंघ व भाजपा के पास रही गांधीनगर जिले की दहेगाम विधानसभा सीट पिछले दो चुनावों से कांग्रेस के हाथों में चली गई थी, जहां भाजपा फिर से काबिज हो गई। कांग्रेस के गढ़ समान जसदण व चोटीला सीट में भी इस बार केसरिया लहराया है।

चुनाव परिणाम आए, कांग्रेस को सब जगह मुंह की खानी पड़ी। 7 में से 5 स्थानों पर भाजपा ने जीत दर्ज की और कांग्रेस को 2 स्थानों पर ही सफलता मिली। इनमें से पांचों के पांच स्थान भाजपा ने कांग्रेस से छीने। ये हैं–जसदान, चोटिला, देहगाम, दंता और सामी हारिज। कांग्रेस अपनी पिछली जीती हुई सिर्फ धारोजी सीट ही बचा पाई। कोदिनार सीट उसने भाजपा से छीन ली। अब गुजरात विधानसभा में भाजपा के सदस्यों की संख्या 122 हो गई है। जबकि कांग्रेस के मात्र 54 विधायक रह गए हैं।

खास बात यह है कि विधानसभा के इन उपचुनावों में नरेन्द्र मोदी कहीं चुनाव प्रचार करने नहीं गए। उन्होंने सिर्फ युवा और अच्छी छवि के प्रत्याशियों का चयन किया। मोदी सरकार के विकास कार्यों और गुजराती अस्मिता पर किए जा रहे हमलों ने भाजपा को जीत दिलाई।

इधर उत्तराखण्ड के विकासनगर में हुए प्रतिष्ठापूर्ण मुकाबले में भाजपा के कुलदीप कुमार पाराशर ने कांग्रेस के पूर्व मंत्री नव प्रभात को लगभग 600 मतों से हराया। यह सीट भाजपा सरकार में मंत्री रहे मुन्ना सिंह चौहान द्वारा पार्टी के निर्णय के विरुद्ध टिहरी से लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए त्यागपत्र देने के कारण रिक्त हुई थी। इस जीत के साथ उत्तराखण्ड विधानसभा में भाजपा के सदस्यों की संख्या बढ़कर 36 हो गई और 70 सदस्यीय विधानसभा में उसे पूर्ण बहुमत प्राप्त हो गया है।

मध्य प्रदेश में भी शिवराज सिंह चौहान का जादू बरकरार है। यहां दो सीटों के लिए उपचुनाव हुए। यह दोनों ही स्थान कांग्रेस के थे। पर भाजपा ने तेंदुखेड़ा सीट कांग्रेस से छीन ली जबकि कांग्रेस गोहद सीट बचाने में सफल रही है।

कांग्रेस के लिए सबसे शर्मनाक स्थिति रही दिल्ली में, जहां हुए उपचुनावों में वह अपनी दोनों सीटें गंवा बैठी। विधानसभा चुनावों में भाजपा की करारी हार और लोकसभा चुनावों में सभी सात की सात सीटों पर हार ने भाजपा को निराशा में डुबो दिया था। हालांकि दिल्ली नगर निगम में वर्चस्व जमाकर भाजपा ने सिद्ध कर दिया था कि दिल्ली उससे दूर नहीं है। पर कांग्रेस सरकार और उसकी 'करिश्माई' कही जाने वाली मुख्यमंत्री श्रीमती शीला दीक्षित के रहते उप चुनावों में दोनों सीटों पर पार्टी की हार जल्दी हजम होने वाली बात नहीं है।

खास बात यह है कि इसमें से द्वारका विधानसभा सीट भाजपा ने कांग्रेस से छीनी है। यहां भाजपा के प्रद्युम्न राजपूत ने कांग्रेस की तिलोत्तमा चौधरी को 11 हजार से अधिक मतों से हराया। यह स्थान कांग्रेस विधायक महाबल मिश्रा द्वारा पश्चिमी दिल्ली से लोकसभा सदस्य चुने जाने के कारण रिक्त हुआ था। 15 सितम्बर को हुई मतगणना में कांग्रेस को दूसरा झटका ओखला में लगा। यहां से विधायक परवेज हाशमी के राज्यसभा सदस्य चुने जाने के बाद हुए उपचुनाव में बाजी मारी राजद के आसिफ मोहम्मद खान ने। उल्लेखनीय यह भी है कि बसपा यहां दूसरे स्थान पर रही और कांग्रेस तीसरे स्थान पर चली गई। दिल्ली के चर्चित नेता रामबीर सिंह बिधूड़ी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी से लड़े और चौथे स्थान पर रहे।

दिल्ली

भाजपा की विजय से कार्यकर्ताओं में उत्साह

लोकसभा के बाद दिल्ली में विधानसभा व नगर निगम के लिए हुए सात चुनावों में भाजपा ने छह पर बाजी मारी है, पहले इनमें से छह सीटों पर कांग्रेस काबिज थी। द्वारका विधानसभा उपचुनाव में जीत से भाजपा नेताओं के हौसले बुलंद हैं।

तीसरी बार दिल्ली में सत्ता हासिल करने वाली कांग्रेस ने हाल ही में संपन्न लोकसभा चुनाव में सातों सीटों पर जीत दर्ज की थी। लेकिन नगर निगम की पांच सीटों पर हुए चुनाव में कांग्रेस को दो और भाजपा को तीन सीटों पर विजय मिली थी। अब एक बार फिर विधानसभा उपचुनाव में द्वारका सीट पर भाजपा की जीत ने पार्टी को उत्साह से भर दिया है। जाहिर है कि अगर भाजपा मजबूत विपक्ष की भूमिका निभाए तो उसका भविष्य बेहतर हो सकता है। गौरतलब है कि कांग्रेस सांसद महाबल मिश्रा ने इसी क्षेत्र से 60 हजार मतों से चुनाव जीता था। इस इलाके से विधानसभा चुनाव में भी भाजपा को 14 हजार मतों से हार का सामना करना पड़ा था, लेकिन इस उपचुनाव में भाजपा ने 11 हजार मतों के अंतर से चुनाव जीत कर कांग्रेस को परेशानी में डाल दिया है। द्वारका विधानसभा से भाजपा उम्मीदवार प्रद्युम्न राजपूत और ओखला से राजद उम्मीदवार आसिफ मुहम्मद खां की जीत ने प्रतिपक्ष के हौसले बुलंद कर दिए हैं।

प्रतिक्रिया

बिजली, पानी, महंगाई और यातायात जैसी समस्याओं से जूझ रही जनता ने कांग्रेस को सबक सिखा दिया है।

& izk- fot; dqekj eYgks=k] ¼izfri{k ds usrk½

जनता ने निगम को कमजोर करने की दिल्ली सरकार की चाल को पूरी तरह से नकार दिया है।

& Mk- dqoj lsu] ¼egkikSj½

बढ़ती महंगाई व क्षेत्र में समस्याओं के अंबार ने दिलाई जीत।

& iz|qEu jktiwr] ¼}kjdk ls fot;h izR;k'kh½

हालांकि देशभर के उपचुनाव परिणामों में भाजपा की जीत के स्वाद को बिहार उपचुनाव परिणामों ने कुछ कसैला कर दिया। यहां 18 सीटों पर हुए उपचुनावों में राजग गठबंधन को मात्र 5 सीटों (जद (यू) 3 तथा भाजपा 2) पर संतोष करना पड़ा। लालू की राष्ट्रीय जनता दल को 6 तथा रामविलास पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी को 3 स्थानों पर सफलता मिली।

हालांकि भाजपा को यहां मात्र 1 सीट का नुकसान उठाना पड़ा। पर बताया जा रहा है कि जद (यू) द्वारा अपने पूर्व प्रत्याशी के परिवार को ही टिकट न देने के निर्णय का उसे खामियाजा उठाना पड़ा। पर परिवारवादी राजनीति के विरुद्ध यह एक अच्छा कदम कहा जा सकता है, भले ही प्रारम्भिक अवस्था में परिणाम सुखद न रहा हो। ■

विजय से कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ा है : राजनाथ सिंह

fo भिन्न राज्यों में विधानसभाओं के चुनावों मे कुछ सीटों के उप–चुनाव में पार्टी के प्रदर्शन पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए भाजपा नेताओं ने कहा है कि इन परिणामों से साफ हो गया है कि पार्टी नीचे की ओर नहीं जा रही है। पार्टी अध्यक्ष श्री राजनाथ सिंह ने कहा कि भाजपा ने हर राज्य में बढ़िया प्रदर्शन किया है और इन उप–चुनावों के परिणामों के बाद अब कोई यह नहीं कह सकता है कि भाजपा नीचे की ओर फिसल रही है। इन चुनावों से साफ है कि गुजरात में कांग्रेस ने ना सिर्फ अपनी जमीन खोई है, बल्कि गुजरात की ही तरह उसने उत्तराखंड और मध्य प्रदेश में भी आधार खोया है। गौरतलब है कि गुजरात में सात सीटों के लिए हुए उप–चुनाव में भाजपा ने पांच और कांग्रेस ने दो सीटों पर जीत हासिल की है। इन सात सीटों मे से पहले छह कांग्रेस के पास और केवल एक भाजपा के पास थी। उत्तराखंड में विकासनगर सीट का उप–चुनाव जीत कर बीजेपी ने प्रदेश विधानसभा में अपने बल पर बहुमत हासिल कर लिया है क्योंकि 70 सदस्यीय सदन में अब उसके पास 36 सीट हो गई हैं। मध्य प्रदेश में दो सीटों के लिए हुए उप–चुनाव में भी बीजेपी ने तेंदुखेड़ा विधानसभा सीट कांग्रेस से छीन ली है, जबकि कांग्रेस ने गोहाद की सीट फिर से जीती है। पार्टी प्रवक्ता श्री रविशंकर प्रसाद ने कहा कि उप चुनावों में कांग्रेस ने अपने 100 दिन के शासन की उपलब्धियों के नाम पर वोट मांगे थे लेकिन जनता ने उसे नकार दिया। गुजरात में भाजपा के शानदार प्रदर्शन से स्पष्ट हो गया है कि जनता की विश्वसनीयता की मुहर पार्टी और मुख्यमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी दोनों पर लग गई है। इन उपचुनावों को ध्यान में रख कर ही कांग्रेस ने आदमखोर कह कर इशरत जहां मामले के बहाने श्री नरेन्द्र मोदी पर निशाना साधा था लेकिन जनता ने श्री नरेन्द्र मोदी में निष्ठा जताई है। लोकसभा चुनाव के बाद हुए उपचुनावों ने बता दिया है कि पार्टी के लिए जीत का सिलसिला बार फिर शुरू हो गया है। ■

उत्तराखंड

विकासनगर उपचुनाव में भाजपा ने लहराया परचम

विकासनगर विधानसभा के लिए सम्पन्न हुए उपचुनाव में जनता ने मुख्यमंत्री श्री रमेश पोखरियाल निशंक सरकार पर भरोसा व्यक्त करते हुए जनादेश भाजपा प्रत्याशी कुलदीप कुमार के पक्ष में दिया है। कुलदीप कुमार ने कांटे के इस मुकाबले में कांग्रेस प्रत्याशी नवप्रभाव को 596 मतों के अंतर से मात दी है। भाजपा, कांग्रेस तथा निर्दलीय मुन्ना सिंह चौहान के लिए प्रतिष्ठा का सवाल बन चुके विकासनगर विधानसभा उपचुनाव में आखिरकार बाजी भाजपा प्रत्याशी कुलदीप कुमार के हाथ लगी। प्रातः आठ बजे से आशाराम वैदिक इंटर कालेज में शुरू हुई मतगणना में पहले तीन चरणों में निर्दलीय प्रत्याशी मुन्ना सिंह चौहान ने भाजपा और कांग्रेस प्रत्याशियों पर बढ़त बनायी लेकिन चौथा चरण शुरू होते ही मुन्ना पिछड़ते चले गये और मुख्य मुकाबले में भाजपा प्रत्याशी कुलदीप कुमार और कांग्रेस प्रत्याशी नवप्रभाव आ गये। अंततः भाजपा के कुलदीप कुमार ने 24934 मत हासिल कर कांग्रेस प्रत्याशी को पराजित कर दिया। इस मुकाबले में कांग्रेस प्रत्याशी को 24338 मत मिले जबकि निर्दलीय प्रत्याशी और निवर्तमान विधायक मुन्ना सिंह को 14804 मतों में ही संतोष करना पड़ा। मुख्यमंत्री निशंक ने इस जीत का श्रेय कार्यकर्ताओं और विकासनगर की जनता को देते हुए उनका आभार व्यक्त किया। विकासनगर विधानसभा कांग्रेस की परम्परागत सीट रही है। पहले ब्रहमदत्त और फिर उनके पुत्र नवप्रभात इस सीट से चुनाव जीतते रहे हैं। 2007 के विधानसभा चुनाव में भाजपा ने यहां स्थानीय नेता मुन्ना सिंह चौहान को टिकट दिया था उस समय मुन्ना भाजपा नहीं बल्कि अपनी छवि के बल पर चुनाव जीते थे।■

राज्य के निर्माण में शहीदों के बलिदान को कभी भुलाया नहीं जा सकता : निशंक

mत्तराखण्ड देश का आदर्श राज्य बने, इसके लिए हम सभी को सामूहिक प्रयास करने होंगे तभी राज्य गठन के उद्देश्यों को पूरा किया जा सकेगा। यह बात मुख्यमंत्री डॉ. रमेश पोखरियाल निशंक ने जोगीवाला में उत्तरांचल उत्थान परिषद के भूमिपूजन कार्यक्रम में कही। मुख्यमंत्री ने परिषद के पुस्तकालय एवं बहुउद्देश्य भवन निर्माण के लिए 11 लाख रूपये धनराशि की सहायता देने की भी घोषणा की।

मुख्यमंत्री डॉ. निशंक ने कहा कि उत्तराखण्ड राज्य के निर्माण में शहीदों एवं आंदोलनकारियों के त्याग एवं बलिदान को कभी भुलाया नहीं जा सकता है। हम सभी को मिलकर उनके सपनों के अनुरूप राज्य का नवनिर्माण करना है। उन्होंने कहा प्रदेश में प्रकृति ने पर्याप्त संसाधन है, जिनके वैज्ञानिक एवं उचित नियोजन की आवश्यकता है, जिसके लिए उन्होंने बुद्धिजीवियों से चिंतन करने की अपील की। मुख्यमंत्री ने कहा कि पर्यटन, जड़ी बूटी, जल विद्युत उत्पादन आदि पर्याप्त संभावनाओं वाले क्षेत्रों में और अधिक कार्य करने की आवश्यकता है, ताकि यहां की जवानी और पानी का सदुपयोग किया जा सके।

मुख्यमंत्री डॉ. निशंक ने कहा कि उत्तराखण्ड देश का आदर्श राज्य बने, इसके लिए हम सभी को मिलजुलकर प्रयास करने होंगे। उन्होंने कहा कि हम ऐसा संकल्प ले, जिससे यह प्रदेश को देश का आदर्श राज्य बने। मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्तमान में जबकि पूरा देश कठिन परिस्थिति से गुजर रहा है, तब लोगों की निगाह प्रदेश की ओर है। उन्होंने कहा कि देश का भाल होने के कारण प्रदेश के विकास के साथ–साथ देश की उन्नति का दायित्व हमारे ऊपर है। देश की सुरक्षा में यहां के सैनिकों ने मिसाल कायम की है। मुख्यमंत्री द्वारा दीप उपाध्याय को जैविक कृषि, विष्णु प्रसाद सेमवाल को वन संरक्षण, हिम्मत सिंह को जड़ी बूटी उपचार करने के क्षेत्र में तथा किशन सिंह भण्डारी मशरूम संरक्षण में कार्य करने के लिए सम्मानित

किया। कार्यक्रम में कृषि मंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने विधायक निधि से 10 लाख रूपये धनराशि परिषद को देने की घोषणा की। इस अवसर पर शारदापीठाधीश्वर जगद्गुरू पूज्य शंकराचार्य ने आशीर्वाद देते हुए कहा कि उत्तरांचल उत्थान परिषद अपने महत्वपूर्ण उद्देश्य को प्राप्त करने में सफल हो। उन्होंने कहा कि यह प्रदेश का सौभाग्य है, कि उन्हे डॉ. निशंक के रूप में युवा मुख्यमंत्री मिले है, जिनका एकमात्र मिशन राज्य का विकास करना है। क्षेत्र प्रचारक शिव प्रकाश ने कहा कि गांव से लोगों का पलायन हो रहा है तथा कृषि भूमि का प्रतिशत भी घटा है, जिसको देखते हुए परिषद ने गांव में शिक्षा, स्वास्थ्य एवं समरसता के विषय को लेकर बीड़ा उठाया है।

इस अवसर पर उत्तरांचल उत्थान परिषद के अध्यक्ष दयालधर जोशी तथा उपाध्यक्ष प्रेमबुढ़ाकाटी ने परिषद के कार्यों पर प्रकाश डाला तथा उपाध्यक्ष दयानंद चंदोलना ने कार्यक्रम की सफलता के लिए सहयोगी उपस्थित जनों का धन्यवाद ज्ञापित किया। कार्यक्रम में पेयजल मंत्री प्रकाश पंत, डॉ. आदित्य आर्य, समाज कल्याण राज्य मंत्री खजान दास, विधायक एवं पूर्व मंत्री अजय टम्टा, विधायक प्रेमचंद अग्रवाल, महापौर नगर निगम विनोद चमोली, सभासद विपिन राणा, प्रधान हरभजन सिंह आनंद सहित अनेक गणमान्य लोग उपस्थित थे। ■

मध्य प्रदेश

भाजपा ने छीना तेंदूखेड़ा

vc ei: fo/kkulHkk e: rktk nyh; fLFkfr	
भाजपा	144
कांग्रेस	69
बसपा	07
भाजश	05
निर्दलीय	03
सपा	01
रिक्त (सोनकच्छ)	01
कुल सीटें	230

मध्यप्रदेश में दो विधानसभा सीटों के लिए हुए उपचुनाव का फैसला भाजपा और कांग्रेस के लिए बराबरी वाला रहा। गोहद में कांग्रेस प्रत्याशी रणवीर जाटव ने भाजपा प्रत्याशी सोबरन जाटव को 22 हजार 571 वोटों से शिकस्त देकर पार्टी की सीट बरकरार रखी जबकि तेंदूखेड़ा में भाजपा प्रत्याशी

भैयालाल पटेल ने कांग्रेस प्रत्याशी विश्वनाथ पटेल को 12 हजार 634 से हराकर कांग्रेस से सीट छीन ली। दोनों ही सीटों पर निकटतम उम्मीदवार के अलावा अन्य सभी की जमानत जब्त हो गई। पिछले साल हुए विधानसभा चुनाव की तुलना में कांग्रेस को एक सीट का नुकसान हुआ है जबकि भाजपा एक सीट के फायदे में रही। गौरतलब है कि गोहद में तत्कालीन कांग्रेस विधायक माखनलाल जाटव की हत्या के कारण सीट खाली हुई थी। जबकि तेंदूखेड़ा सीट पर उपचुनाव तत्कालीन विधायक राव उदयप्रताप सिंह को लोकसभा चुनाव में सांसद चुन लिए जाने के बाद उनके विस से इस्तीफे के कारण हुआ। ■

चीनी घुसपैठ पर सरकार की चुप्पी चिंताजनक : राजनाथ सिंह

Hkk जपा अध्यक्ष राजनाथ सिंह ने भारतीय क्षेत्र में चीनी घुसपैठ संबंधी खबरों पर गंभीर चिंता जताई है और केन्द्र पर इस मुद्दे पर चुप्पी साधने का आरोप लगाया है।

सिंह ने कहा कि कांग्रेस ने इस मुद्दे पर चुप्पी क्यों साधे रखी है। सैन्य प्रमुख को बोलना पड़ा है। जनरल दीपक कपूर को चिंता जाहिर करना पड़ी है, यह दर्शाता है कि स्थिति गंभीर है। राजनीतिक नेतृत्व को यह चिंता जाहिर करना थी।

उन्होंने कहा कि सरकार को भारतीय क्षेत्र में चीनी सेना की लगातार धुसपैठ के बारे में चीन के समक्ष अपना विरोध दर्ज कराना चाहिए।

श्री सिंह ने कहा कि चीन ने राजदूत को तलब किया जाना चाहिए और विरोध दर्ज कराया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि भारत चीन पर राजनीतिक दबाव भी बना सकता है।

भाजपा नेता ने कहा कि 1962 में भी जब चीन ने हमारे देश में घुसपैठ की थी, तब भी भारत का रूख इनकार वाला था। जनरल कपूर ने गत सप्ताह कहा था कि चीनी घुसपैठ हुई है लेकिन उन्होंने वक्तव्य को यह कहकर नरमी दी कि वास्तविक नियंत्रण रेखा के प्रति समझ में अंतर होने के कारण दोनों देशों की सेनाएं ऐसा करती है। बहरहाल, उन्होंने चीनी घुसपैठ और भारतीय क्षेत्र में चट्टानों पर 'चीनी' लिखे जाने पर चिंता जताई। पहली बार ऐसा हुआ कि चट्टानों को 'चीनी' लिखकर पोता गया।

जनरल कपूर ने कहा कि भारत ने चीन के सीमा सुरक्षा कर्मियों के साथ बैठक के दौरान उनके समक्ष यह मुद्दा उठाया है।

सरकार से इस मामले में अपना रूख स्पष्ट करने की मांग करते हुए राजनाथ सिंह ने कहा कि भारत एक बार 1962 में भुगत चुका है जब तत्कालीन सरकार भारतीय क्षेत्र में घुसपैठ मानने को तैयार नहीं थी। उस युद्ध में भारत को शर्मनामक हार का सामना करना पड़ा और चीन ने भारतीय क्षेत्र पर अतिक्रमण कर लिया।

श्री सिंह ने याद दिलाया कि तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि चिंता करने जैसा कुछ नहीं है। उन्होंने सब कुछ छिपाने की कोशिश की जिसके चलते भारत को गंभीर नतीजे भुगतने पड़े।

भाजपा अध्यक्ष ने कहा कि हाल ही में नौसन्य प्रमुख अब सेवानिवृत्त सुरीश मेहता ने भी चीन के मामले में भारत की स्थिति के बारे में कहा था। उन्होंने कहा कि हमारा न तो चीन से बल के मामले की बराबरी करने का इरादा है और न ही क्षमता है। लेकिन श्री सिंह ने आगाह किया कि अपनी सेना के आधुनिकीकरण के बाद चीन पड़ोसी देश में क्षेत्र को लेकर अपने दावों पर जोर डाल सकता है।

समाज सेवा में बालआश्रम का योगदान सराहनीय : डा. रमन सिंह

छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह ने राजधानी रायपुर में विगत लगभग 85 वर्षों से संचालिक बालआश्रम में आज नवरात्रि के दूसरे दिन अनाथ बच्चों को अपनी ओर से भोजन कराया और वस्त्र भी वितरित किए। मुख्यमंत्री ने इन बच्चों के साथ जमीन पर बैठकर भोजन भी ग्रहण किया। प्रदेश के गृहमंत्री श्री ननकी राम कंवर भी उनके साथ कार्यक्रम में शामिल हुए।

डॉ. रमन सिंह ने आश्रम परिसर स्थित मंदिर में पूजा अर्चना की और इन बच्चों को आशीर्वाद प्रदान करते उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की। डॉ. सिंह ने समाज सेवा के क्षेत्र में बाल आश्रम के योगदान की प्रशंसा करते हुए कहा कि संस्था द्वारा यहां अनाथ बच्चों को अच्छी शिक्षा के साथ अच्छे संस्कार भी दिए जा रहे हैं। डॉ. सिंह ने इन बच्चों का हौसला बढ़ाते हुए उम्मीद जताई कि वे आगे चलकर देश और समाज की बेहतरी के लिए महत्वपूर्ण कार्य करेंगे। उल्लेखनीय है कि बाल आश्रम की स्थापना वर्ष 1924 में की गई थी।

मुख्यमंत्री ने आज वहां आयोजित कार्यक्रम में संस्था को छत्तीसगढ़ में बेसहारा बच्चों की मदद के लिए चार अन्य जिलों में भी आश्रम संचालित करने का सुझाव दिया और कहा कि इसके लिए राज्य शासन द्वारा संस्था को निःशुल्क जमीन दी जाएगी। डॉ. रमन सिंह ने कहा कि राज्य के बस्तर संभाग में नक्सल हिंसा के कारण अनेक बच्चे अनाथ हो गए हैं, जिन्हें गोद लेकर संस्था उनकी बेहतरी के लिए बहुत कुछ कर सकती है। उन्होंने कहा कि रायपुर के कचहरी चौक स्थित बाल आश्रम का अपना एक गौरवशाली इतिहास है। ■

भारत-चीन संबंधों पर श्वेतपत्र जारी हो : भाजपा

भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता तथा संसद सदस्य श्री रवि शंकर प्रसाद द्वारा 18 सितम्बर, 2009 को जारी प्रेस वक्तव्य

Xत कुछ महीनों के दौरान भारत की सीमा पर चीनी घुसपैठ की घटनाओं में बहुत ही चिंताजनक तथा अशुभ वृद्धि हुई है। विश्वसनीय सूचना के अनुसार वर्ष 2008 में 233 बार चीनी घुसपैठ हुई तथा गत तीन महीनों के दौरान 76 बार घुसपैठ हुई। इसमें न केवल वास्तविक नियंत्रण रेखा का उल्लंघन शामिल है बल्कि, चीन की सेना द्वारा भारत के भू–क्षेत्र में घुस आने का और अनेक बार हेलीकॉप्टर द्वारा अतिक्रमण करना शामिल है। जब ऐसी घटनाएं हो रही हैं तब यह जानकर व्यथा होती है कि जिन लोगों के कंधों पर हमारी विदेश नीति को प्रबंधित करने का भार है, वे सादगी दर्शाने की प्रतिस्पर्धात्मक राजनीति में उलझे हुए हैं तथा वे भारत के मध्यम वर्ग को पशु वर्ग के रूप में चित्रित कर रहे हैं। ये ऐसी बातें है जिनकी घोर निंदा की जानी चाहिए।

चीनी घुसपैठ न केवल लद्दाख या उत्तर पूर्वी क्षेत्र – विशेषतया अरूणाचल प्रदेश में, बल्कि अब ये सिक्किम के आस–पास भी हो रही है। यह बहुत ही चिंताजनक स्थिति हैं, क्योंकि राजग शासनकाल के दौरान चीन ने सिक्किम को औपचारिक रूप से भारत का हिस्सा स्वीकार कर लिया था। यह बेहद कष्टदायक और हैरानी पैदा करने वाली बात है कि भारत सरकार इसकी जान–बूझकर अनदेखी कर रही है तथा विदेश मंत्री ने इस तथ्य के बावजूद इसको सार्वजनिक रूप से मामूली घटना बताया है कि चीन के आक्रामक रवैये के पीछे कुत्सित इरादे और उद्देश्य हैं जो कि निम्नलिखित से साफ प्रकट होते हैं :

1. चीनी राजदूत ने अरूणाचल प्रदेश को बार–बार विवादित क्षेत्र घोषित किया है, जिसको चीनी नेताओं ने भी समय–समय पर पुनरूक्त किया है।
2. चीन अरूणाचल प्रदेश में तवांग पर इस आधार पर विशेष रूप में दावा करता है कि छठे दलाई लामा का जन्म वहीं हुआ था। साथ ही चीन वर्तमान दलाई लामा के भारत दौरे का भी सख्त विरोध करता है। भाजपा दलाई लामा के दौरे का पूरी तरह समर्थन करती है।
3. जब भी कोई भारत का वरिष्ठ राजनैतिक नेता – यथा प्रधानमंत्री, यहां तक कि राष्ट्रपति भी अरूणाचल राज्य का दौरा करते हैं तभी चीन हमेशा इसका विरोध करता है।
4. अब अरूणाचल प्रदेश के तथाकथित विवाद को अंतर्राष्ट्रीय रूप दिए जाने के जान–बूझकर कुत्सित इरादे व्यक्त किए जा रहे हैं, जो इस तथ्य से स्पष्ट है कि चीन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट के माध्यम से एशिया विकास बैंक को यह स्वीकार न करने देने में सफल हो गया था कि अरूणाचल प्रदेश भारत का भाग है। ऐसा इस तथ्य के बावजूद हुआ कि चीनी प्रधानमंत्री के विगत दौरे के दौरान इस बात पर सहमति हुई थी कि हर मुद्दे को द्विपक्षीय रूप में सुलझाया जाएगा। यहां तक कि, भारत के पारंपरिक मित्रों जैसे जापान आदि ने भी भारत के हितों के विरूद्ध मत दिया था।
5. वार्ता (ढांचागत या अन्यथा) के कई दौरों का भी कोई परिणाम नहीं निकला है।
6. चीन तथा पाकिस्तान दोनों के द्वारा सीमा के उल्लंघन में एक समय पर वृद्धि की गई है, जो भारत के विरूद्ध चिंताजनक टीम वर्क दर्शाता है।
7. हाल में चीनी थिंक–टैंक द्वारा एक लेख छापा था कि चीन की सामरिक सुरक्षा के लिए भारत को बीस अलग–अलग देशों में विघटित किए जाने की जरूरत है। चीनी स्थापना ने इसका कोई स्पष्ट खंडन नहीं किया था।
8. अतिवादी समूहों विशेषकर उल्फा को चीन के समर्थन की रिपोर्ट लगातार मिलती हैं।

इन सब बातों का संचयी संकेत वाकई अशुभ और परेशान करने वाला है। फिर भी सरकार का पूरा रवैया घोर उपेक्षाभरा बना हुआ है। इस घटनाक्रम को कम आंकने के जान–बूझकर प्रयास क्यों किए जा रहे हैं? चीन के साथ संबंधों की वर्तमान स्थिति क्या है? ये भटकाव और विचलन क्यों किया जा रहा है? क्या सरकार इस भटकाव को काबू में करने में अक्षम है? 1962 के कडुवे अनुभव के संदर्भ में देश को यह सब जानने और आश्वस्त होने का हक है। भाजपा बातचीत का तथा संबंधों के सामान्यीकरण का समर्थन करती है किंतु ऐसा जानबूझकर जमीनी हकीकत की, बार–बार की धमकियों की अनदेखी करके और भारत की संप्रभुता तथा क्षेत्रीय अखंडता पर सौदेबाजी करके नहीं किया जाना चाहिए।

ekx

तदनुसार भाजपा की मांग है कि भारत सरकार भारत–चीन संबंधों के पूरे आयामों पर तत्काल एक श्वेत–पत्र प्रकाशित करे, जिसमें सीमा पर हमारी तैयारी के बुनियादी ढांचे को सुधारा जाना तथा सुदृढ़ किया जाना शामिल हो। आज यह याद किए जाने की जरूरत है कि श्री अटल बिहारी वाजपेयी की पहल के कारण भारत सरकार से 1962 में तैयारी न किए जाने के कारण हुई अपमानजनक पराजय के बारे में श्वेत–पत्र प्रकाशित करने पर जोर नहीं दिया गया था।

भाजपा यह मांग भी करती है कि देश को इस बारे में विश्वास में लिया जाए कि किस प्रकार की धमकियां मिल रही हैं और सरकार उन्हें किस रूप में लेती हैं तथा वह देश की सुरक्षा के बारे में क्या सुधारात्मक उपाय कर रही है। ऐसा करना सादगी और ट्वीटिंग की राजनीति से कहीं अधिक जरूरी है।■

केन्द्र सरकार बचत को ढोंग न बनाए : भाजपा

बचत पर सांकेतिक पहल कांग्रेस पार्टी का मात्र एक छलावा है। यह मूलरूप से देश के समक्ष बढ़ते महंगाई को नजरअंदाज करने का एक विफल प्रयास है। हम किसी भी प्रयास का जो बचत के दृष्टिकोण से है तथा सरकार द्वारा हर क्षेत्र में लगाया जायेगा उसका स्वागत करेंगे। परंतु वर्त्तमान में किये जा रहे कांग्रेस पार्टी का यह प्रयास महंगाई को छिपाने का ढोंग है। एक ओर सरकार जहां अकाल और महंगाई को बचत से जोड़कर एक संवेदनशील विषय को तुच्छ करने का प्रयास कर रही है वहीं इस बात को नकारा नहीं जा सकता कि कांग्रेस की यह पुरानी परिपाटी रही है कि दर्द और भुखमरी का राजनीतिक इस्तेमाल करे। एक ओर जहां कांग्रेस बचत की बात कर रही है वहीं सामान्य नागरिक बढ़ती महंगाई के कारण जबरन महंगाई के कटौती को अपने आप पर पहले हीं थोप चुका है।

भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता व सांसद, श्री राजीव प्रताप रूडी द्वारा 15 सितम्बर, 2009 को जारी प्रेस विज्ञप्ति

क्या प्रणव मुखर्जी जी यह बतायेंगे कि जब उनके मंत्रालय के एक वरिष्ठ सदस्य आधे दर्जन से अधिक कैबिनेट की बैठकों में भाग नहीं लेते है या फिर रेल मंत्रालय के सैकड़ों संचिकाओं को महीनों तक नहीं देखा जाता अथवा उन संचिकाओं को कोलकाता विशेष दूत द्वारा हवाई जहाज या रेल से भेजा जा रहा है तो उस पर क्या खर्च आता है। सरकार में काम नहीं करना क्या अपव्यय नहीं है?

हालांकि संप्रग सरकार के राजनीतिक महकमे को बचत करने का संवाद कुछ हद तक विचारणीय है परंतु संप्रग सरकार कृपया अपने पीछे में जमा उन हजारों करोड़ों रूपये को अपव्यय अथवा फिजुलखर्ची एवं प्राक्कलन वृद्धि, जो उर्जा, सिंचाई, राष्ट्रीय उच्च पथ एवं अन्य संरचनात्मक योजनाओं में वर्षों तक हुआ है, उसका जवाब देना चाहेंगे। आज देश में लगभग 301 परियोजनाओं के कार्यान्वयन में विलम्ब है जिससे देश को 48,961 करोड़ का भारी नुकसान हुआ है, इसके लिए कौन जिम्मेदार है?

क्या प्रणव मुखर्जी जी यह बतायेंगे कि जब उनके मंत्रालय के एक वरिष्ठ सदस्य आधे दर्जन से अधिक कैबिनेट की बैठकों में भाग नहीं लेते है या फिर रेल मंत्रालय के सैकड़ों संचिकाओं को महीनों तक नहीं देखा जाता अथवा उन संचिकाओं को कोलकाता विशेष दूत द्वारा हवाई जहाज या रेल से भेजा जा रहा है तो उस पर क्या खर्च आता है। सरकार में काम नहीं करना क्या अपव्यय नहीं है?

भारतीय जनता पार्टी किसी प्रकार के खर्च कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करेगी लेकिन कांग्रेस सरकार को इन प्रस्तावों को राजनीतिक ईमानदारी के साथ रखना होगा।

कहीं ऐसा तो नहीं है कि बचत के अभियान के इस बोलबाले में सरकार राष्ट्र के समक्ष संभावित भविष्य में आने वाले भूचाल के लिए अपना आधार बना रही है जो बढ़ती महंगाई और अकाल से उत्पन्न स्थिति के कारण देश को ग्रस्त करेगा। वैसे भी हाल में वरिष्ठ केन्द्रीय मंत्रियों के बयान जो खाद्य भंडारण के संबंध में है उससे पहले ही बाजार में जमाखोरी बढ़ गई है और बढ़ती महंगाई पर इसका सीधा प्रभाव पड़ रहा है।

कल तक संप्रग के वरिष्ठ मंत्री पांच सितारा होटलों के ऐशो आराम से बाहर नहीं निकलना चाहते थे वो अचानक आज बचत के नुमाईंदे बनकर अपना उपदेश दे रहे है। हजारों बार सामान्य सांसद एवं अन्य महत्वपूर्ण व्यक्ति शताब्दी ट्रेन की यात्रा करते हैं परंतु गांधी परिवार की इस यात्रा को बचत का मानक मान रहे हैं। स्वाभाविक तौर पर जब पूर्व में कभी इनमें यात्रा न किया हो तो यह समाचार ही है। हमें विश्वास है कि भविष्य में भी गांधी परिवार शताब्दी में हीं यात्रा करना पसंद करेगा।

सोनिया गांधी आज इकोनॉमी श्रेणी में चलना पसंद कर रही है परंतु उनको यह नहीं पता कि इस बचत अभियान में देश को कितना खर्च वहन करना पड़ रहा है। संप्रग सरकार जहां बचत की बात कर रहा है वहीं सार्वजनिक जीवन में अनेक ऐसे लोग है जो स्वतः सामान्य रूप से बचत व्यवहार करते है। राजग के वरिष्ठ समाजवादी नेता श्री जॉर्ज फर्नान्डिस ऐसे राजनीति व्यक्ति रहे है जिन्होंने अपने राजनीतिक जीवन में कभी भी एक सांसद की हैसियत से या पूर्व में केन्द्रीय मंत्री रहते हुए कभी भी उच्च श्रेणी में हवाई यात्रा नहीं की है। कांग्रेस का यह तेवर संदेह युक्त है और उनके द्वारा

कांग्रेस महासचिव राहुल गांधी के तमिलनाडु यात्रा के संदर्भ में अखबारों में प्रकाशित हुआ है कि उन्होंने अपनी तीन दिनों की तमिलनाडु यात्रा पर एक करोड़ से भी अधिक रूपया खर्च किया। एक तरफ तो श्री गांधी मितव्ययता का राग अलाप रहे है, वहीं दूसरी ओर सिर्फ तीन दिनों में ही देश की जनता की खून–पसीने की कमाई का करोड़ों रूपया खर्च कर डालते हैं।

बचत के सवाल पर छाती पीटना किसी भी सामान्य भारतीयों को महंगाई के समक्ष प्रभावित नहीं करेगा। यह ढोंग देर सवेर उजागर हो ही जायेगा।

मितव्यता पर डपोरशंखी बयान बंद हों

कांग्रेस पार्टी जो महात्मा गांधी के नीति और सिद्धांतों पर चलने का दावा करती है, राजनीति में मितव्ययता के सिद्धांत को पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया है। केन्द्रिय विदेश राज्य मंत्री शशि थरूर ने हवाई जहाज के इक्नॉमिक क्लास मे यात्रा करने वाले यात्रियों की तुलना भेड़– बकरियों से करके देश के मध्यवर्गीय लोगों के जीवन शैली और रहन–सहन पर घोर आघात कर उन्हें अपमानित किया है। ऐसा अपमान इस देश में आज तक किसी भी शासन काल में किसी भी शासक अथवा राजनेता ने नहीं किया। शशि थरूर की यह टिप्पणी कि कांग्रेसी राज की मानसिकता को दर्शाती है, देश के करोड़ों भारतवासियों के आत्मस्वाभिमान को गहरा आघात पहुंचाती है।

कांग्रेस महासचिव राहुल गांधी के तमिलनाडु यात्रा के संदर्भ में अखबारों में प्रकाशित हुआ है कि उन्होंने अपनी तीन दिनों की तमिलनाडु यात्रा पर एक करोड़ से भी अधिक रूपया खर्च किया। एक तरफ तो श्री गांधी मितव्ययता का राग अलाप रहे है, वहीं दूसरी ओर सिर्फ तीन दिनों में ही देश की जनता की खून–पसीने की कमाई का करोड़ों रूपया खर्च कर डालते हैं। भारतीय जनता पार्टी का यह स्पष्ट मानना है कि श्री राहुल गांधी, सोनिया गांधी एवं अन्य कांग्रेसी नेताओं का यह डपोरशंखी बयान केवल जनता को भरमाने और ठगने के लिए है एवं जनता का ध्यान देश की समस्याओं से अन्यत्र बटाने के लिए है। देश की जनता कांग्रेस पार्टी की दोहरी नीति और आचरण से पुरी तरह अवगत है।

भारतीय जनता पार्टी सरकार के द्वारा उठाये गये मितव्ययता के ठोस अभियान का समर्थन करेगी। बशर्ते सरकार की नियत एवं आचरण स्वच्छ एवं समान हो। उदाहरण के तौर पर एन0डी0ए0 शासन काल में मितव्ययता बरतने हेतु 2003 संवैधानिक संशोधन के द्वारा केन्द्र एवं राज्य में मंत्रिमंडल के आकार को सीमित किया गया था, जिससे आज देश को हजारों करोड़ों रूपये की बचत हुई है। भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस सरकार से देश में व्याप्त महंगाई से निपटने के लिए ठोस कदम उठाने के लिए मांग करती है, न कि क्षुद्र राजनीतिक लाभों के लिए अनाप–शनाप बयानबाजी करने की। ■

केन्द्र सरकार का एक सौ दिन का एजेंडा आम आदमी के साथ छलावा - नरेन्द्र सिंह तोमर

भोपाल 15 सितम्बर, 09 भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और सांसद श्री नरेन्द्र सिंह तोमर ने यूपीए सरकार के 100 दिन के एजेंडा को जनता के साथ छलावा बताया है। उन्होंने कहा कि केन्द्र सरकार ने अपने सौ दिन की कार्ययोजना में देश के अविकसित पिछड़े क्षेत्रों में चिकित्सा महाविद्यालयों की स्थापना को प्राथमिकता देने और चिकित्सा महाविद्यालयों की स्थापना में मापदंडों को शिथिल करने की घोषणा की है। लेकिन मध्यप्रदेश के पिछड़े अंचल बुंदेलखण्ड (सागर संभाग) में 2007 में स्वीकृत चिकित्सा महाविद्यालय की सारी सुविधाएं चाक चौबंद हो जाने पर भी केन्द्र सरकार और चिकित्सा परिषद भारत सरकार ने अभी तक मान्यता प्रदान नहीं की जिससे चिकित्सा महाविद्यालय में प्रथम वर्ष के प्रवेश में अवरोध उत्पन्न हो गया है।

श्री नरेन्द्र सिंह तोमर ने कहा कि आजादी के छः दशकों में बुंदेलखण्ड की कांग्रेस ने सुधि नहीं ली। इससे बुंदेलखण्ड के जिलों सागर, पन्ना, छतरपुर, दमोह, टीकमगढ़, दतिया स्वास्थ्य सुविधाओं में पिछड़ गए हैं। प्रदेश में भाजपा की सरकार के गठन के पश्चात इस दिशा में गंभीरतापूर्वक विचार कर ठोस उपाय किये गये हैं। भाजपा सरकार ने दो वर्ष पूर्व सागर में चिकित्सा महाविद्यालय की स्थापना की मंजूरी दी और भवन निर्माण का कार्य तेजी से आरंभ किया। भवन परिसर बनकर तैयार हो चुका है। अध्यापन स्टाफ तैनात किया जा चुका है। उपकरण आ चुके हैं, प्रवेश की तैयारियां संपन्न हो चुकी हैं। लेकिन चिकित्सा महाविद्यालय की स्थापना का श्रेय प्रदेश की भाजपा सरकार को न मिलने पाए इसलिए केन्द्र सरकार प्रवेश किये जाने में रोड़ा अटका रही है। मान्यता नहीं दिया जाना बुंदेलखण्ड की जनता के साथ पक्षपात है। केन्द्र सरकार खुद अपने न्यूनतम साझा कार्यक्रम से मुकर गयी है।

श्री नरेन्द्र सिंह तोमर ने कहा कि चिकित्सा परिषद और केन्द्र सरकार के राजनीतिक दुराग्रह के कारण बुंदेलखण्ड की जनता में भारी आक्रोश है। बुंदेलखण्ड क्षेत्र के सांसदों और विधायकों को 16 सितम्बर को दिल्ली में एमसीआई के विरोध में धरना आंदोलन करने के लिए विवश होना पड़ रहा है। केन्द्र सरकार अपने 100 दिन के एजेंडा का पालन करें और सागर चिकित्सा महाविद्यालय को मान्यता प्रदान करे। केन्द्र सरकार सहानुभूतिपूर्वक विचार करके बुंदेलखण्ड की जनता की आकांक्षाओं को पूरा करने में तत्परता दिखा सकती है। ■

श्रीमान एस.एम. कृष्णा आप पुनः बिना सोचे-समझे बोल पड़े

Hkk रत सरकार के विदेश मंत्री श्री एस.एम. कृष्णा ने न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा की बैठक के समय वॉल स्ट्रीट जनरल के साथ एक साक्षात्कार में कहा : "अफगानिस्तान में संघर्ष का कोई सैनिक समाधान नहीं है और नाटो (NATO) के युद्धक ऑपरेशनों के स्थान पर तालिबान के साथ राजनीतिक समझौता किया जाना चाहिए।" भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता तथा संसद सदस्य श्री रवि शंकर प्रसाद ने एक प्रेस वक्तव्य जारी कर कड़ी आपत्ति दर्ज करते हुए कहा कि यह बहुत ही अर्थगर्भित बयान है जो भारत के विदेश मंत्री ने दिया है और जिसके दूरगामी परिणाम होंगे।

उन्होंने कहा कि तालिबान आज भय पैदा करता है और वह नरसंहार, हत्या, उत्पीड़न तथा मध्यकालीन हिंसा के उग्रतम और नृशंस रूप का सहारा लेता है। उनकी दुनिया में असहमति, संवाद, मानव सम्मान तथा मानव अधिकारों के प्रति चिंता के लिए कोई स्थान नहीं है। उनके उत्पीड़न की सर्वाधिक यंत्रणा स्त्रियों को सहनी पड़ती है। यह ऐसी यंत्रणा है, जिस पर कोई भी सभ्य समाज लज्जित हो उठेगा। इसके अतिरिक्त तालिबान नंगे आतंक और निष्ठुर हत्याओं के माध्यम से इस क्षेत्र के विभिन्न भागों में अपना प्रभाव क्षेत्र बढ़ाना चाहता है।

उनका एजेंडा स्पष्ट रूप में भारत को अस्थिर करना है। इस प्रयोजन की सिद्धि के लिए तालिबान के प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष समर्थन से अनेक आतंकी समूह देश के अंदर सक्रिय हैं और हमारे देश पर हमला कर रहे हैं। यह एक सुविज्ञात तथ्य है कि पाकिस्तानी स्थापना में कुछ आईएसआई जैसे तत्व तालिबान के महत्वपूर्ण संरक्षक हैं।

यह याद किए जाने की जरूरत है कि गत वर्ष काबुल में भारतीय दूतावास पर और अफगानिस्तान में कार्यरत भारतीय इंजीनियरों पर जो हमला हुआ था उसकी योजना तथा कार्यान्वयन तालिबान द्वारा की गई थी। पाकिस्तान के साथ उस हमले का संबंध होने की व्यापक रिपोर्टें आई थीं। ऐसा इसलिए किया जा रहा है कि अफगानिस्तान की औसत जनसंख्या का भारत के प्रति गहरा सौहार्द है क्योंकि अफगानिस्तान के पुर्ननिर्माण में हमारे देश ने सार्थक सहायता की है और मानवतावादी प्रयास किए है।

हमें याद रखने की जरूरत है कि जब अफगानिस्तान में सत्ता तालिबान के हाथ में थी तब IC-814 का का दुर्भाग्यपूर्ण हाईजैकिंग हुआ था और इसकी व्यूह–रचना तथा समर्थन कंधार स्थित तालिबानियों द्वारा किया गया था। कश्मीर से संबंध रखने वाले अनेक आतंकवादियों को तालिबान ने अपने शिविरों में प्रशिक्षण दिया था। तालिबान की विचारधारा को किसी भी प्रकार की मान्यता देना और उनके साथ किसी भी प्रकार का समझौता करना भारत की सुरक्षा के लिए गंभीर संकट पैदा करने वाला है।

भाजपा प्रवक्ता ने कहा कि इन सुस्पष्ट तथ्यों के आलोक में भारतीय विदेश मंत्री की टिप्पणी न केवल चिंताजनक है, बल्कि गैर–जिम्मेदाराना भी है, जिसकी जितनी भी भर्त्सना की जाए कम है। विदेश मंत्री को स्पष्ट करना चाहिए कि तालिबान के साथ बातचीत और समझौता करने से उनका क्या अभिप्राय है।

तालिबान से संबंध रखने वाले अनेक आतंकवादी समूह और अन्य भारत–विरोधी समूह हमारे देश के विरूद्ध आतंकवादी मंसूबों के साथ बेखौफ हमले कर रहे हैं। कल ही कश्मीर में सेना के एक मेजर सहित अनेक जवानों को मौत के घाट उतारा गया है। क्या श्रीमान कृष्णा इन समूहों के साथ भी बातचीत का समर्थन करते हैं ?

सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्रश्न स्वयं तालिबान के उद्देश्यों के बारे में उठता है – उस तालिबान के, जो उत्पीड़न, नरसंहार, हत्या और निष्ठुर खून–खराबे का हिमायती है। यदि तालिबान पर छोड़ दिया जाए तो वह भारत को विखंडित करने के लिए किसी भी सीमा तक चला जाएगा। फिर भी भारत के विदेश मंत्री जी परिणामों को सोचे बिना अनाप–शनाप टिप्पणी करते हैं। उनको होमवर्क किए बिना और देश के सामरिक हितों की लागत पर असंगत बोलने की आदत हो गई है।

भाजपा मांग करती है कि प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह को तुरंत स्पष्ट करना चाहिए कि विदेश मंत्री की ऐसी घोर गैर–जिम्मेदाराना टिप्पणियों के बारे में भारत सरकार की क्या स्थिति है। ऐसा किया जाना इसलिए भी जरूरी है कि श्रीमान कृष्णा की ऐसी "विद्वततापूर्ण टिप्पणी" भारत की सुविज्ञात नीति के विरूद्ध है।

देश को अपनी और अपने सामरिक हितों की सुरक्षा के लिए सभी प्रयास करने की आवश्यकता है। एक अतिशय विद्वेषी चीन, एक शत्रुतापूर्ण पाकिस्तान, बांग्लादेश भारत के विरूद्ध अतिवादी करतूतों की शरणस्थली बन गए हैं। नेपाल में चल रही सतत अनिश्चितता भी एक चुनौती प्रस्तुत कर रही है।

वायुसेना अध्यक्ष एयर चीफ मार्शल पी.वी. नाइक के इस बयान के परिप्रेक्ष्य में कि भारत की वायुसेना क्षमता अपर्याप्त है तथा वह चीनी वायुसेना के मात्र एक–तिहाई है, यह बहुत ही चिंता पैदा करने वाला खुलासा है। इससे हमारे बयानों की पुष्टि होती है कि सशस्त्र सेनाओं को साजो–सामान और हथियारों से सुसज्जित करने के लिए संप्रग सरकार द्वारा पर्याप्त ध्यान नहीं दिया जा रहा है। देश की सुरक्षा के लिए इस काम को पहली प्राथमिकता के आधार पर किया जाना चाहिए। ■

जनता परिवर्तन के मूड में

gekj: loknnkrk }kjk

eहाराष्ट्र विधानसभा के चुनाव 13 अक्टूबर को होने जा रहे हैं और 22 अक्टूबर को वोटों की गिनती होगी। विभिन्न राजनीतिक दलों ने अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं। इस चुनाव में मुख्य मुकाबला वर्तमान सत्तारूढ़ कांग्रेस–राकांपा गठबंधन और भाजपा–शिवसेना गठबंधन के बीच है। तीसरा मोर्चा (रिपब्लिकन वामपंथी लोकतांत्रिक मोर्चा), बहुजन समाज पार्टी एवं महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना भी अपनी प्रभावी उपस्थिति दर्ज कराने को लेकर चुनाव मैदान में सक्रिय हैं। महाराष्ट्र में कुल 288 विधानसभा सीटें हैं, और किसी भी राजनीतिक दल या गठबंधन को महाराष्ट्र में अगली सरकार बनाने के लिए 144 सीटें जीतने के लिए आवश्यक है। वर्तमान में, कांग्रेस और राकांपा गठबंधन पिछले दस सालों से महाराष्ट्र के राज्य पर सत्तारूढ़ है। वर्ष 2004 के चुनावों में शिवसेना ने 171 और भाजपा ने 117 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे थे। गठबंधन को 119 सीटें हासिल हुईं थीं जबकि कांग्रेस–राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (राकांपा) गठबंधन का 139 सीटों पर विजयी रहा था। कांग्रेस ने पिछली बार गठबंधन के तहत 157 सीटों पर अपने प्रत्याशी खड़ा कर 69 सीटों पर जीत हासिल की थी जबकि राकांपा ने उसे आवंटित 124 में से 71 सीटों पर जीत दर्ज कर कांग्रेस को कुछ पीछे छोड़ दिया था। कांग्रेस और राकांपा ने अपने–अपने कोटे से सात सीटें रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया (आठवले) जैसे सहयोगी दलों के लिए छोडी थीं, जिनमें से वे एक सीट ही जीत पाई थी।

महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव को लेकर भाजपा और शिवसेना के बीच समझौता हो गया है। भारतीय जनता पार्टी के महासचिव गोपीनाथ मुंडे ने बताया, 'महाराष्ट्र विधानसभा की 288 सीटों में से शिव सेना 169 सीटों पर और भाजपा 119 सीटों पर चुनाव लड़ेगी।' रंग शारदा में आयोजित एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए मुंडे ने कहा, 'हमारा सपना कांग्रेस–राकांपा की सरकार को बाहर कर महाराष्ट्र में सत्ता में आने का है। मुख्यमंत्री कौन बनता है यह बात गैरजरूरी है।' वहीं, कांग्रेस 174 और उसकी गठबंधन सहयोगी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी 114 सीटों पर अपने प्रत्याशी खड़े करेगी। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना 100 से ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ेगी। एक महत्वपूर्ण राजनीतिक घटनाक्रम में पूर्व सांसद रामदास आठवले के गुट सहित विभिन्न रिपब्लिकन दलों ने आपसी विलय कर 'एकीकृत रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया' बनाने के बाद वामपंथी और अन्य दलों के साथ मिलकर राज्य में तीसरा मोर्चा बना लिया है। नए मोर्चे का नाम 'रिपब्लिकन वामपंथी लोकतांत्रिक मोर्चा(रिवलोमो) रखा गया है और इसमें कांग्रेस, राकांपा, भाजपा और शिवसेना को छोड़कर अन्य सभी दलों को साथ लाने का प्रयास करते हुए अभी तक समाजवादी पार्टी, शेतकरी कामगार पार्टी और जनता दल (सेक्यूलर) समेत 22 दलों को शामिल किया जा चुका है। तीसरा मोर्चा कांग्रेस के वोटों में सेंधमारी कर सकता हैं। इस बीच, बहुजन समाज पार्टी (बसपा) ने इस नवगठित तीसरे मोर्चे में शामिल होने से स्पष्ट इन्कार करते हुए कहा है कि वह सभी 288 सीटों पर अपने उम्मीदवार खड़े करेगी। पार्टी महासचिव और राज्य के मुम्बई–ठाणे तथा कोंकण क्षेत्र के प्रभारी प्रोफेसर सुरेश माने का कहना है कि उनकी पार्टी की नीति रही है कि वह किसी मोर्चे में तब तक शामिल नहीं होगी जब तक उसका नेतृत्व उसके हाथ में नहीं हो। बसपा ने पिछली बार भी किसी अन्य दल से गठबंधन किए बिना ही विधानसभा की 272 सीटों पर अपने उम्मीदवार खड़े किए थे लेकिन उनमें कोई भी जीत हासिल नहीं कर पाया था। पार्टी को उस चुनाव में लगभग चार प्रतिशत मत मिले थे। हाल के लोकसभा चुनाव में राज्य में उसका जनाधार बढ़कर 4.75 प्रतिशत हो गया है।

परिसीमन में नई बनी एवं खत्म हुई सीटों के कारण महाराष्ट्र के कई दिग्गज नेताओं के परंपरागत क्षेत्र ही समाप्त हो गए हैं। एक अनुमान के मुताबिक परिसीमन के कारण 89 मौजूदा विधायकों के क्षेत्र बिगड़ गए हैं। इनमें सबसे ज्यादा 30 विधायक कांग्रेस के, 20 राकांपा के, 19 शिवसेना के और 16 भाजपा के हैं। इनमें से कई विधायक अपनी–अपनी पार्टियों में काफी महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। परिसीमन के कारण शहरों और क्षेत्रों के समीकरण भी बदल गए हैं। जैसे मुंबई से सटे ठाणे जनपद में पहले सिर्फ

11 विधानसभा सीटें थीं। यहां अब 24 सीटें हो गई हैं। मुंबई उपनगर में पहले 17 सीटें थीं। अब 26 हो गई हैं। लेकिन मुख्य मुंबई में सीटें घट कर 17 से 10 पर पहुंच गई हैं। इससे माफिया सरगना अरुण गवली जैसों की परंपरागत सीट गायब हो गई है। कोंकण में सीटों की संख्या 65 से 75 हो गई है, जबकि विदर्भ में 66 से घट कर 62, पश्चिम महाराष्ट्र में 62 से घट कर 58 एवं उत्तर महाराष्ट्र में 49 से घट कर 47 हो गयी है।

खुफिया ब्यूरो (आईबी) ने महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के दौरान आतंकी संगठन लश्कर–ए–तैयबा या अंडरवर्ल्ड की ओर से हमला किए जाने की चेतावनी दी है। खुफिया सूचना के मुताबिक लश्कर किसी बड़े नेता को निशाना बनाने की साजिश रच रहा है। एक वरिष्ठ खुफिया अधिकारी ने कहा है कि दाऊद इब्राहिम का अंडरवर्ल्ड नेटवर्क भी चुनाव के दौरान कुछ उम्मीदवारों के समर्थन या विरोध में सक्रिय हो सकता है। अधिकारी के मुताबिक चेतावनी खास तौर पर 13 अक्टूबर को होने वाले विधानसभा चुनाव के सिलसिले में है। इस दौरान दिल्ली से विभिन्न दलों के बड़े नेता मुंबई और महाराष्ट्र के दूसरे हिस्सों में प्रचार के लिए पहुंचेंगे।

भाजपा ने बेलगाम महंगाई को कांग्रेस की असफलता का मुद्दा बनाया है। वरिष्ठ भाजपा नेता राम नाइक ने कहा कि आम आदमी बढ़ती कीमतों की गर्मी को महसूस कर रहा है। आर्थिक मोर्चे पर केंद्र विफल हो गया है। हमारी पार्टी इसे बड़े चुनावी मुद्दे के तौर पर पेश करेगी। उन्होंने कहा कि बढ़ती कीमतों के बावजूद केंद्र की मुद्रास्फीति की आधिकारिक दर तेजी से घट रही है। नाइक ने केंद्रीय कृषि मंत्री शरद पवार पर हालात से निपटने में लापरवाही का आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार ने पहले ही संकेत दिया है कि कीमतें और बढ़ सकती हैं।

इसके अलावा कृषि उत्पादन भी उत्साहजनक नहीं रहा है। महाराष्ट्र में आम लोग तमाम दिक्कतों से जूझ रहे हैं। मुम्बई में आतंकी हमला, स्वाइन लू, बिजली–पानी तथा विदर्भ में किसानों द्वारा जारी आत्महत्या जैसे मुद्दों के चलते कांग्रेस–राकांपा गठबंधन को नुकसान उठाना पड़ सकता है। ■

विकास पचा नहीं पा रहे विपक्षी

शिमोगा में मुख्यमंत्री श्री बी.एस. येड्डियूरप्पा ने कहा कि सत्तारूढ़ भाजपा सरकार की विभिन्न क्षेत्रों में विकास संबंधी उपलब्धियों को पचा न पाने के कारण विपक्षी दल सरकार को अस्थिर करने की कोशिश में लगे हैं और राज्य की जनता को गुमराह कर रहे हैं।

श्री येड्डियूरप्पा ने कहा कि पिछले कुछ दिनों से कांग्रेस व जद (ध) चर्च पर हुए हमले को अस्त्र की तरह इस्तेमाल करके सरकार पर अनर्गल आरोप लगा रहे हैं। राज्य में कानून व व्यवस्था की स्थिति बेहतर है।

हाल में इंडिया टुडे द्वारा 9 राज्यों में करवाए सर्वेक्षण में कर्नाटक को कानून व व्यवस्था में प्रथम स्थान मिला है। इसके बावजूद विपक्षी दलों के नेता कानून एवं व्यवस्था की आड़ लेकर अल्पसंख्यकों के मन में उलझन व भय पैदा करने में लगे हैं।

उन्होंने कहा कि राज्य में जब कांग्रेस व जद (ध) की सरकार सत्ता में थी उस वक्त भी देवालयों, मस्जिदों व चर्चों पर हमले हुए थे। राजधानी बेंगलूरू के हेब्बगुड़ी में स्थित चर्च पर हुए हमले को इतना तूल देने की आवश्यकता नहीं थी। चर्च पर हुए हमले की घटना के बारे में पहले ही सीओडी जांच के आदेश दिए जा चुके हैं।

इसके अलावा पुलिस विभाग के आला अधिकारियों की बैठक बुलाकर इस तरह के हमलों में दोषी पाए जाने वाले शरारती तत्वों को गिरफ्तार करके उनके खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं।

कानून व्यवस्था यदि भंग हुई तो इसके लिए जिलाधिकारियों व जिला पुलिस अधीक्षकों को जिम्मेदार ठहराया जाएगा। जिन विषयों पर सदन में बहस चल रही है उनके बारे में गली– कूचों में चर्चा करके राज्य की जनता को भ्रमित करने का विपक्षी नेता प्रयास कर रहे हैं। वे किसी भी मसले पर विपक्षी नेताओं के साथ खुलकर बहस करने को तैयार हैं।

उन्होंने कहा कि जिम्मेदारी के पद पर बैठे विपक्ष के नेताओं को गैर जिम्मेदाराना तरीके से बयान देने से बचना चाहिए। जद (ध) के राष्ट्रीय अध्यक्ष देवेगौड़ा व प्रदेश अध्यक्ष कुमार स्वामी को आड़े हाथों लेते हुए श्री येड्डियूरप्पा ने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री देवेगौड़ा को अपनी गरिमा के अनुरूप बयानबाजी करनी चाहिए। देवेगौड़ा पर किसानों के नाम पर घड़ियाली आंसू बहाने का आरोप लगाते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि देवेगौड़ा ने कहा कि राज्य के किसानों की स्थिति को देखकर खुदकुशी करने को जी चाहता है।

इस तरह के बयान देकर देवेगौड़ा किसानों का मनोबल तोड़ने व उनको परोक्ष रूप से आत्महत्या करने को उकसा रहे हैं।

देश में पहली बार किसी सरकार ने कृषि व ग्रामीण विकास जैसे मसलों पर चर्चा के लिए विशेष अधिवेशन बुलाया है। लेकिन इस मसले पर चर्चा करने के बजाय विपक्षी नेता चर्च पर हमले की घटना व कानून व्यवस्था जैसे मसलों को उठाकर जनता का ध्यान भंग करना चाहते हैं। ■

कांग्रेस और भाजपा के बीच मुकाबला

V रुणाचल प्रदेश में 13 अक्टूबर को होने वाले विधानसभा चुनावों के लिए तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। राज्य में विधानसभा की कुल 60 सीटें हैं, जिसमें से 59 सीटें अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित हैं। अरुणाचल प्रदेश में सात लाख 50 हजार 575 मतदाता हैं। प्रदेश में मतदाता पहचान–पत्र का काम 87 प्रतिशत पूरा हो चुका है। पिछले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने 34, भाजपा ने 9, अरुणाचल कांग्रेस तथा एनसीपी को दो–दो तथा 13 सीटों पर निर्दलीय जीते थे। निर्दलियों में अधिकांश विद्रोही उम्मीदवार थे जो कांग्रेस से टिकट न मिलने पर मैदान में उतरे थे। सरकार बनने के बाद एक मात्र विपक्षी दल भाजपा के सभी नौ विधायकों ने पाला बदलकर अलग ग्रुप बनाया और अपना समर्थन सत्तारूढ़ कांग्रेस को दे दिया। इस प्रकार अरुणाचल देश का ऐसा पहला राज्य है, जहां की विधानसभा विपक्षविहीन थी।

अरुणाचल प्रदेश में विधानसभा के लिए प्रथम चुनाव 1978 में हुए थे। विधानसभा में सदस्यों की कुल संख्या 30 थी। भाजपा ने 1984 में विधानसभा के लिए छह प्रत्याशी खड़े हुए थे उनमें से उसका एक प्रत्याशी जीता और तीन सीटों पर उसने द्वितीय स्थान प्राप्त किया है। 1990 में अरुणाचल प्रदेश विधानसभा की सीटों की संख्या 60 कर दी गई। 1990 तक अरुणाचल प्रदेश में मुख्य रुप से दो ही राजनीतिक दल रहे, प्रथम कांग्रेस और द्वितीय पीपुल्स पार्टी आफ अरुणाचल प्रदेश। यद्यपि पीपीए में भी कांग्रेस से निकल कर ही लोग आये थे लेकिन उसने प्रदेश में क्षेत्रीयता के आधार पर अपने लिए स्थान बनाने का प्रयास किया।

30 अगस्त, 2003 को अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री गेगांग अपांग, जिन्होंने कांग्रेस से टूट कर अपनी अरुणाचल कांग्रेस का गठन किया था, अपने समस्त विधायकों समेत भाजपा में ही शामिल हो गये। इस प्रकार अरुणाचल प्रदेश में अल्पकाल के लिए प्रथम भाजपा सरकार बनीं। लेकिन जल्दी ही गेगांग अपांग अपनी मूल पार्टी में चले गये और 2004 का विधानसभा चुनाव भाजपा ने अपने बलबूते लड़ा और कांग्रेस को करारी टक्कर दी। कांग्रेस केवल 34 सीटें जीत सकी। भाजपा ने 9 और स्वतंत्र प्रत्याशियों ने 13 सीटों पर विजय हासिल की।

भाजपा ने 1995 के विधानसभा चुनाव में 15 प्रत्याशी खड़े किये। यद्यपि पार्टी को सीट तो कोई हासिल नहीं हुई लेकिन उसने 3.37 प्रतिशत मत प्राप्त किये। इसके बाद 1999 के विधान सभा चुनाव में भाजपा ने 23 प्रत्याशी खड़े किये। सीट उसे इस बार भी कोई नहीं मिली लेकिन उसका मत प्रतिशत 10.83 हो गया। 2004 के विधानसभा चुनाव में भाजपा ने 39 प्रत्याशी मैदान में उतारे।

उसे विधानसभा में 9 सीटें प्राप्त हुई और 9 पर ही उसके प्रत्याशी द्वितीय स्थान पर रहे।

राज्य में विधानसभा की कुल 60 सीटें हैं, जिसमें से 59 सीटें अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित हैं। अरुणाचल प्रदेश में सात लाख 50 हजार 575 मतदाता हैं। अरुणाचल प्रदेश में मतदाता पहचान–पत्र का काम 87 प्रतिशत पूरा हो चुका है। पिछले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने 34, भाजपा ने 9, अरुणाचल कांग्रेस तथा एनसीपी को दो–दो तथा 13 सीटों पर निर्दलीय जीते थे। निर्दलियों में अधिकांश विद्रोही उम्मीदवार थे जो कांग्रेस से टिकट न मिलने पर मैदान में उतरे थे।

एक दो सीटें तो भाजपा ने बहुत ही कम मतों से हारीं। 2004 तक आते आते भाजपा का प्रभाव क्षेत्र भी नागालैण्ड के साथ लगते दो जिलों चांगलांग और तिराप को छोड कर लगभग सारे अरुणाचल प्रदेश में स्थापित हो गया। 2004 के विधानसभा चुनाव में कामेंग क्षेत्र की 12 विधानसभा सीटों में से 5 पर भाजपा प्रत्याशी जीते और दो स्थानों पर दूसरे नंबर पर रहे।

इसी प्रकार सिआंग क्षेत्र की 13 सीटों में से दो पर भाजपा प्रत्याशी जीते और 3 पर दो नंबर पर रहे। सुबानश्री क्षेत्र की 11 सीटों में से 1 पर भाजपा ने जीत प्राप्त की और दो पर उसके प्रत्याशी दूसरे नंबर पर रहे। दिबांग घाटी की तीन सीटों में से भाजपा प्रत्याशी एक सीट पर दूसरे नंबर पर रहा। लोहित जिले की 5 सीटों में से 1 पर भाजपा प्रत्याशी जीता और 1 पर दूसरे नंबर पर रहा।

कांग्रेस इस विधानसभा चुनाव में अपने कार्यकाल में हुए विकास कार्यों के सहारे मैदान में उतर रही है तो भाजपा कांग्रेस शासन में हुए भ्रष्टाचार को प्रमुख चुनावी मुद्दा बना रही है। ■

जरूरी है एकीकृत खाद्यान्न बजट

& fo".knÙk ukxj

जिन खाद्य जिंसों का बफर स्टॉक नहीं रखा जाता, उनकी जमाखोरी होने लगती है। फिर बढ़ती है महँगाई और कालाबाजारी। उसके बाद इन्हें रोकने की मशक्कत की जाती है। इस प्रकार से बने एकीकृत खाद्य बजट को रेल बजट के समान संसद में प्रस्तुत करना होगा ताकि विभिन्न क्षेत्रों से आए जन प्रतिनिधियों को देश की खाद्यान्न सुरक्षा के तहत किए जा रहे इस मॉडल से परिचित कराया जा सके।

> ***उद्योग संगठन एसोचैम द्वारा किए गए एक अध्ययन के अनुसार वर्ष 2008 में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन 5 हजार करोड़ रुपए से शुरू हुआ। वर्ष 2011–12 तक गेहूँ का उत्पादन 80 लाख टन, चावल का एक करोड़ टन और दालों का 20 लाख टन बढ़ोतरी का लक्ष्य रखा गया था, लेकिन यह मिशन अपने लक्ष्य से भटक गया और दालों का उत्पादन घटता गया।***

भारत अपनी घरेलू माँग पूरी करने के लिए हर वर्ष तीस लाख टन दलहनों का आयात करता है। देश में करीब 1.4 करोड़ टन चावल का उत्पादन होता है, जबकि उसकी माँग 1.8 लाख करोड़ टन की है। पिछले दो महीनों के मुकाबले दालों की कीमतें 40 से 60 प्रतिशत के प्रीमियम के साथ बिक रही हैं। अरहर 50 रुपए से बढ़कर 90 रुपए, मसूर 70 रुपए और उड़द 60 रुपए प्रति किलो तक पहुँच गई है। दाल और रोटी का रिश्ता इस हद तक टूट चुका है कि दाल की खपत 1960 के दशक में प्रति व्यक्ति 29 किलोग्राम के मुकाबले घटकर 2009 में 11 किलोग्राम रह गई है। चीनी का हाल तो और बुरा है। जमाखोरी और सट्टेबाजी के कारण चीनी का मूल्य 35 रुपए प्रति किलो को भी लाँघ गया है। यह भी तब जबकि इस साल चीनी का उत्पादन 150 लाख टन हुआ है और पिछले वर्ष की बची हुई 80 लाख टन जुड़ने के बाद देश में 230 लाख टन का स्टॉक था। जबकि देश में चीनी की खपत 213 लाख टन की है। इसी के साथ समय–समय पर कृषि मंत्री शरद पवार द्वारा विश्व बाजार में शक्कर चीनी कम होने जैसे भाषणों से महाराष्ट्र के सटोरिये सक्रिय होते रहे।

देश के लिए एकीकृत खाद्यान्न बजट अब तो इसलिए भी आवश्यक है कि समय–समय पर सरकार द्वारा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन और सार्वजनिक वितरण प्रणाली को मजबूत करने के नाम पर किए गए प्रयोग अपना उद्देश्य पूरा नहीं कर सके हैं। उद्योग संगठन एसोचैम द्वारा किए गए एक अध्ययन के अनुसार वर्ष 2008 में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन 5 हजार करोड़ रुपए से शुरू हुआ। वर्ष 2011–12 तक गेहूँ का उत्पादन 80 लाख टन, चावल का एक करोड़ टन और दालों का 20 लाख टन बढ़ोतरी का लक्ष्य रखा गया था, लेकिन यह मिशन अपने लक्ष्य से भटक गया और दालों का उत्पादन घटता गया। सार्वजनिक वितरण प्रणाली में व्याप्त भ्रष्टाचार ने इसे इतना पंगु बना दिया है कि पिछले तीन वर्षों में देश के कुल 15 प्रतिशत राशन दुकानों के लाइसेंस रद्द किए गए और चौदह हजार लोग गिरफ्तार हुए। इस परिवेश में सरकार ने नया राष्ट्रीय सुरक्षा खाद्य अधिनियम लाकर नई योजना प्रस्तुत की है जिसके अनुसार प्रत्येक भूखे परिवार को 25 किलो खाद्यान्न तीन रुपए की दर से मिलने का प्रावधान रखा गया है। इतना ही नहीं, सार्वजनिक वितरण प्रणाली पूरे देश में समान रूप से उपलब्ध भी नहीं है जैसे पूर्वोत्तर राज्यों में यह प्रणाली अस्तित्व में ही नहीं है।

उपरोक्त परिस्थितियों में सभी देशवासियों के लिए खाद्यान्नों की उपलब्धता, मूल्य स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए एकीकृत खाद्यान्न बजट योजना के मुख्यतः तीन चरण होंगे। पहले चरण में जिला स्तर पर जरूरी खाद्यान्न पदार्थों की खपत या माँग और आपूर्ति का बजट बनाया जाए। इस प्रकार देश के 600 से अधिक जिलों के खाद्यान्न बजट के आधार पर केंद्र सरकार समूचे देश के लिए माँग और पूर्ति की मात्रा के आधार पर विभिन्न वस्तुओं के उत्पादन, उपलब्धता आदि का आकलन करे। यदि मौसम की मार के कारण आपूर्ति और माँग का अंतर बढ़े तो उसके अनुसार अन्तरराष्ट्रीय बाजार में कीमतें बढ़ने की पूर्व योजना लक्ष्य तैयार करे। अब तक का हमारा कटु अनुभव यह रहा है कि इस प्रकार की आपूर्ति और खपत के अंतर को पाटने के लिए जब भी सरकार आयात करती है तब अन्तरराष्ट्रीय बाजार में कीमतें बढ़ जाती हैं। वर्तमान में खाद्यान्न आयात निजी व्यापारियों के द्वारा किया जाता है, जबकि बाकी आयात एनएमटीसीए एसटीएस और पीईसी जैसे तीन सार्वजनिक उपक्रमों और प्रमुख सहकारिता संस्था नेफेड के द्वारा किया जाता है।

एकीकृत बजट की अवधारणा के तहत निजी, सार्वजनिक और सहकारिता क्षेत्रों द्वारा किए जा रहे आयात को एक ही एजेंसी के तहत लाना होगा ताकि समय पर देश में माँग और पूर्ति के अंतर को पाटा जा सके। दूसरे चरण में विभिन्न खाद्यान्न पदार्थों की माँग और आपूर्ति की पृष्ठभूमि में गेहूँ, चावल, दालों इत्यादि की वसूली के लिए लाभकारी समर्थन मूल्य और बोनस इत्यादि की बुआई के पीछे सरकारी घोषणाओं को अंजाम देना होगा। तीसरे और अंतिम चरण में हमें समय–समय पर बफर स्टॉक बनाने की योजना पर अमल करना होगा। अब तक तो दलहन, चीनी, खाद्य तेल और मोटे अनाज के बफर स्टाक के लिए भी खास परवाह नहीं की जा सकी है। वैश्विक आर्थिक रुझानों और शोध से जुड़ी संस्थान नोमूरा

ग्लोबल इकानोमिक के अनुसार जिन खाद्य जिंसों का बफर स्टाक नहीं रखा जाता, उनकी जमाखोरी होने लगती है। फिर बढ़ती है महँगाई और कालाबाजारी। उसके बाद इन्हें रोकने की मशक्कत की जाती है।

इस प्रकार से बने एकीकृत खाद्य बजट को रेल बजट के समान संसद में प्रस्तुत करना होगा ताकि विभिन्न क्षेत्रों से आए जन प्रतिनिधियों को देश की खाद्यान्न सुरक्षा के तहत किए जा रहे इस मॉडल से परिचित कराया जा सके। लेकिन, नया खाद्यान्न बजट बनाते समय पुरानी कमियों को दूर करते हुए कुछ पूर्व आवश्यकताओं को भी ध्यान में रखा जाना चाहिए।

इन जरूरतों में एक तो मूल्य सूचकांक को जनसाधारण के उपयोग ढाँचे को परिलक्षित करना होगा। यह समझ से परे है कि जब मुद्रास्फीति शून्य से नीचे है तब खाद्यान्न की 12.7 प्रतिशत की मुद्रास्फीति की परस्पर विरोधी प्रकृति, सरकारी महँगाई और बाजार की महँगाई किस प्रकार तालमेल बैठा सकेगी?

एकीकृत बजट अर्थात् आम जनता की जरूरत के सभी किस्म के अनाजों की चिंता करने वाला बजट। अभी जो बजट पेश किया जाता है, उसमें गेहूँ और चावल की चिंता ही खास तौर पर की जाती है। बाकी अनाजों का जिम्मा राज्य सरकार पर छोड़ दिया जाता है। एकीकृत बजट में न केवल पूरे देश के लिए अनाज का आकलन किया जाता है बल्किए उसके इंतजाम पर भी जोर दिया जाता है। यह प्रचलन शुरू हो जाए तो हर थाली में रोटी–दाल का रिश्ता बना रह सकता है।

आपूर्ति के प्रमुख स्रोत खेती को हमें सेज (स्पेशल इकॉनोमिक जोन) की वर्तमान व्यवस्था से भी जोड़कर देखने की जरूरत है। पिछले दिनों प्रसिद्ध वैज्ञानिक डॉ. एमएस स्वामीनाथन ने सुझाव दिया कि विशेष आर्थिक क्षेत्र के समान विशेष कृषि क्षेत्र (स्पेशल एग्रीकल्चरल जोन) का गठन किया जाना चाहिए, जहां इन क्षेत्रों में मिट्टी के लवणीकरण, भूजल स्तर में गिरावट, खरपतवारों की अधिकता, कीटनाशकों के अत्यधिक उपयोग जैसी समस्याओं का तत्काल समाधान ढूंढना होगा।■

(लेखक प्रसिद्ध अर्थशास्त्री हैं)

चीन पर प्रधानमंत्री का बयान भ्रामक : कलराज मिश्र

phन पर प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का बयान भ्रामक है। उन्होंने सीमा पर घुसपैठ का जो तर्क मीडिया पर मढ़ा है वह बेबुनियाद है। भाजपा सांसद कलराज मिश्र ने कहा कि प्रधानमंत्री के बयान पर विपक्ष सतर्क नजरिया अपनाएगा। भाजपा इस मामले को संसद में रखेगी। भारतीय सीमा में चीनी घुसपैठ संबंधी खबरों पर प्रधानमंत्री का इंकार देश को भ्रमित करने की कोशिश है। मीडिया को लिखने की शैली में बदलाव लाने की उनकी सीख यह बताता है कि दाल में कहीं कुछ काला है।

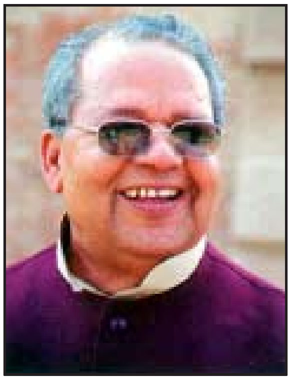

श्री मिश्र ने कहा कि सारा देश यह जानता है कि भारत के अरूणाचल प्रदेश को अपना हिस्सा मानने का बयान चीन दे चुका है। उधर केन्द्र सरकार इस विषय पर आंख–कान बंद रखने की सलाह दे रही है। जबकि चीन हिंद महासागर तक में अपने पैर पसारने का प्रयास कर रहा है। उन्होंने अपील की कि देश की जनता चीनी सामान की खरीददारी न करे। उन्होंने कहा कि वस्तुस्थिति जानने के लिए सीमाई इलाके का दौरा करके वहां के निवासियों से वस्तुस्थिति जाननी चाहिए।

भाजपा सांसद ने कहा कि देश में महंगाई की जिम्मेदार कांग्रेस है। केन्द्र सरकार के मुखिया खुद कहते हैं कि महंगाई अभी और बढ़ने की संभावना है। ऐसे में महंगाई की मार झेल रही जनता पर अभी और बोझ पड़ेगा तो जनता का हाल क्या होगा। मिश्र ने कहा कि उधर उत्तर प्रदेश की बसपा सरकार की महत्वाकांक्षी योजना गंगा एक्सप्रेस के खिलाफ भाजपा 'पोल खोलो' अभियान जल्द ही चलाएगी। 'गंगा एक्सप्रेस वे' योजना के नाम पर कृषि योग्य भूमि को सरकार दलबल की ताकत से जबरन हथियाने का जो प्रयास कर रही है उसे पूरा होने नहीं दिया जाएगा। भाजपा गंगा एक्सप्रेस वे पर बड़ा आंदोलन शुरू करेगी। बिहार प्रदेश के भाजपा प्रभारी श्री कलराज मिश्र ने कहा कि अदालत की अवमानना के बावजूद राज्य सरकार गंगा एक्सप्रेस वे के लिए किसान की भूमि पर हकदारी पर आमादा है। इस विषय पर किसानों ने शिकायतें भी की हैं। नोएडा से बलिया गंगा एक्सप्रेस वे के निर्माण के विरूद्ध भाजपा किसानों के साथ मिलकर जल्द आंदोलन शुरू करने के लिए सड़क पर होगी। पूरे प्रदेश में भाजपा व किसान मिलकर गंगा एक्सप्रेस वे विरोध मार्च निकालेंगे।

एक साक्षात्कार में सांसद श्री कलराज मिश्र ने बताया कि बसपा की सरकार एससी–एसटी एक्ट का दुरूपयोग कर बड़े पैमाने पर राजनीतिकरण करने का प्रयास कर रही है। इससे जातीय उन्माद फैलने की आशंका प्रबल बनती जा रही है।

इस पर भाजपा ने जनता को आगाह किया है। राज्य सरकार जातिवाद के आधार पर अफसरों का तबादला कर रही है। उन्होंने कहा कि राज्य में सूखे की स्थिति से किसान व आम जनता परेशान है वहीं 60 से 70 फीसद कृषि योग्य भूमि पानी न मिलने के कारण उत्पादन में कमी आई है। खाद्यान्न संकट पूरे देश को झेलना पड़ेगा।

केन्द्र सरकार सूखे की जांच के लिए अफसरों को प्रदेश में दौड़ा रही है। लेकिन अफसर छोटे काश्तकार किसानों से न मिलकर सिर्फ धनाढ्य किसानों की जमीनों का दौरा कर लौट रहे हैं। उससे किसानों का भला होने वाला नहीं है।■

लोकतंत्र को थरूरों से बचाना जरूरी

fo".kxIr

e हात्मा गांधी बैरिस्टर थे। वे साउथ अफ्रीका में रंग भेद के खिलाफ आवाज उठा कर पूरी दुनिया के लिए विशेष बन गये थे। दुनिया की सुखसुविधाएं जुटाना उनके लिए बड़ी बात नहीं थी और पूरी दुनिया उन्हें हाथोंहाथ लेने के लिए तैयार बैठी थी। परतंत्रता के विषय से आहत होकर गांधी स्वदेश लौटे और देखा कि मेरे देशवासियों के तन पर वस्त्र तक नहीं हैं। उन्होंने सिर्फ लंगोटी धारण कर ली। लंगोटी के हथियार से गांधी जी न केवल भारतीयों के दिल में बसे बल्कि अंग्रेजों को भगा कर स्वतंत्रता तक दिलायी। चरखा का संदेश उनका स्वयं की सिद्धि और आचरण से जुड़ा हुआ था। गांधी जी ने हमें दिखाया था कि एक जन प्रतिनिधि और नेतृत्वकर्ता का आचरण और व्यवहार कैसा होना चाहिए। महात्मा गांधी के देश में शशि थरूर जैसा जनप्रतिनिधि है और मंत्री भी है जो देशवासियों को 'भेड–बकरी' कहता है। ऐसे जन प्रतिनिधि और मंत्री पर देश को शर्म नहीं आयेगी? विमानों में इकोनॉमी क्लास में सफर करने वालों शशि थरूर ने 'भेड़–बकरी' कहा है। कल्पना कीजिए अगर उनका सामना देश के उन लाखों लोगों से होता जो भूखे और नंगे हैं, उन्हें ये क्या कहेंगे? 'भेड़–बकरी' शब्द पर व्यापक प्रतिक्रिया हुई है, वह कहीं से भी अस्वाभाविक नहीं है। विपक्षी दलों ने इस्तीफा तक भी मांगा है। लेकिन देश की आम जनता और विपक्षी दल सिर्फ अपनी प्रतिक्रिया ही तो जता सकते हैं। कार्रवाई करनी तो कांग्रेस के पास है। कांग्रेस का प्रचंड बहुमत है। इसलिए उसने लीपापोती शुरू कर दी है। खेद जता देने मात्र से थरूर का पाप धुल जायेगा? आम जनता और विपक्ष को कांग्रेस को हटाने या सबक सिखाने का मौका तो पांच वर्ष बाद ही आयेगा। तब तक शशि थरूरों की दिन–दुगुनी–रात चौगुनी तरक्की कौन रोक सकता है।

शशि थरूरों जैसी राजनीतिक संस्कृति भारत में ही चल सकती है, जहां पर राजनीतिक पार्टियां जनादेश हासिल करने के बाद जनता को रौंदने और उनकी इच्छाओं की कब्र बनाने का काम करती हैं। शशि थरूर अगर अमेरिका या यूरोप में मंत्री होते तो निश्चित तौर पर मानिये कि उनका मंत्री पद उसी समय चला गया होता जब उनका बयान और सोच सामने आयी थी। ब्रिटेन में सांसद और मंत्री सार्वजनिक परिवहन का इस्तेमाल करते हैं, फिजूलखर्ची और शान–शौकत दिखाने पर जनता का बुलडोजर चलाने का डर भी होता है। लेकिन हमारी राजनीतिक संस्कृति में शुचिता और स्वच्छता का अभाव तेजी से देखा जा सकता है। जनप्रतिनिधि अहंकार और आडम्बर में डूब जाते हैं। सही या गलत रास्ते से धन और सुख–सुविधाएं हासिल करना उनका एक मात्र लक्ष्य हो जाता है। उन्हें आम जनता की तरह जीना पसंद नहीं होता है। इसलिए कि जनप्रतिनिधि बनते ही वे विशेष हो जाते हैं। संसद और विधानसभाओं की कई धाराएं भी उन्हें विशेष बना देती हैं। उन्हें महंगी गाड़ियां चाहिए, सुरक्षाकर्मियों की फौज चाहिए, विमानों से स्पेशल क्लास में यात्रा करने की सुविधाएं चाहिए। कभी देखने की कार्यसंस्कृति विकसित ही नहीं हुई है कि जन प्रतिनिधि या फिर सरकार देखे कि राजनीतिक नौकरशाह मानदंड से बाहर जाकर सुख–सुविधाएं उपभोग तो नहीं कर रहे हैं। अगर मीडिया या अन्य माध्यमों में ऐसी खबरें आती भी हैं तो भी लीपापोती का हथियार लहरा जाता है।

शशि थरूर जैसी शख्सियतों का राजनीति में चमकना भी एक विमर्श का विषय है। शशि थरूर कोई पूर्ण राजनीतिज्ञ हैं भी नहीं। राजनीति से उनका कोई सरोकार दूर–दूर से नहीं था। वे नौकरशाह संस्कृति की शख्सियत हैं। नौकरशाह संस्कृति में आम जनता कहां ठहरती है। नौकरशाह संस्कृति में जिम्मेदारी किसी के साथ नहीं होती है। अपने पक्ष में सभी रियायतें और सुविधाएं बनाकर रखना इनकी कार्यशैली होती है।

शशि थरूर जैसी शख्सियतों का राजनीति में चमकना भी एक विमर्श का विषय है। शशि थरूर कोई पूर्ण राजनीतिज्ञ हैं भी नहीं। राजनीति से उनका कोई सरोकार दूर–दूर से नहीं था। वे नौकरशाह संस्कृति की शख्सियत हैं। नौकरशाह संस्कृति में आम जनता कहां ठहरती है। नौकरशाह संस्कृति में जिम्मेदारी किसी के साथ नहीं होती है। अपने पक्ष में सभी रियायतें और सुविधाएं बनाकर रखना इनकी कार्यशैली होती है। शशि थरूर संयुक्त राष्ट्र संघ की चाकरी में रहे हैं। संयुक्त राष्ट्रसंघ की चाकरी में ये कौन से तीर मारे थे, यह मालूम नहीं है। संयुक्त राष्ट्रसंघ न केवल शांति के लिए बल्कि भूख–बेकारी अस्पृश्यता आदि के खिलाफ सामाजिक–राजनीतिक और आर्थिक अभियान चलाता है। ऐसी जगहों पर चाकरी करने के बाद भी कोई आम जनता के लिए भेड़–बकरी शब्द का प्रयोग करता है तो उसकी पूरी सोच और अनुभव पर सवाल क्यों नहीं उठेगा? चूंकि ऐसे लोग न केवल चालाक होते हैं बल्कि प्रबंधन तंत्र में भी माहिर होते

हैं। इन्होंने प्रचारित–प्रसारित और स्थापित कराया कि ये वैश्विक कूटनीति के तीसमार खां हैं। भारत ने इन्हें संयुक्त राष्ट्रसंघ के महासचिव बनाने की कूटनीतिक एक्सरसाइज ही नहीं की थी बल्कि वैश्विक स्तर पर शशि थरूर के राजनीतिक कौशल का गुणगान भी हुआ था। बान की मून के सामने इनकी दावेदारी ठहरी नहीं। कल्पना कीजिए अगर ये महानुभाव संयुक्त राष्ट्रसंघ के महासचिव बन जाते तो भारत की कैसी छवि बनाते? भूखे, नंगे, अस्पृश्यता से जूझ रहे लोग क्या इनके लिए धरती का कोढ़ के समान नहीं होते?

शशि थरूरों से कांग्रेस भरी हुई है। एमएस कृष्णा, मुरली देवड़ा जैसे जनता के खेवनहारों का भी चेहरा नहीं देखा जाना चाहिए। एसएम कृष्णा कर्नाटक के मुख्यमंत्री और महाराष्ट्र के राज्यपाल रह चुके हैं। इतने अनुभव वाले राजनीतिक शख्सियत भी पंच सितारा होटलों में रहने पर प्रतिदिन एक लाख रूपये खर्च करता है तो यह भारतीय लोकतंत्र और गरीब जनता का उपहास ही है। मुरली देवड़ा को देश की जनता की नहीं बल्कि रिलायंस घरानों की चिंता होती है। पेट्रोलियम पदार्थों की कीमत कैसे बढ़े, इसके एक्सरसाइज में मुरली देवड़ा का शामिल होना क्या किसी से छिपा हुआ है? शशि थरूर का यह भी कहना कई सवाल खड़ा करता है कि वे अपने पैसे से पंच सितारा होटल में ठहरे हुए थे। क्या उनकी ऐसी आय है या फिर घोषित सम्पत्ति है जिसके माध्यम से वे प्रतिदिन एक लाख रूपया सिर्फ ठहरने में खर्च कर सकते हैं? यह भी बात सामने आयी है कि कोई बड़ी कम्पनी शशि थरूर के पंच सितारा होटल में ठहरने का खर्च उठा रही थी।

यह बात सच है तो यह और भी गंभीर है। वह कम्पनी किस उद्देश्य से शशि थरूर पर इतनी बड़ी राशि खर्च कर रही थी? क्या इसका पता नहीं लगाया जाना चाहिए। कम्पनियां दलाल राजनीतिज्ञों और नौकरशाहों पर लाखों–करोड़ों लुटाती हैं। मकसद साफ होता है नियम–कानूनों को दरकिनार कर अपने लिए बड़ी–बड़ी निविदाएं आदि हासिल करना, ताकि उनके आर्थिक भंडार और भर सकें। इतना ही नहीं बल्कि उनका हित भी संरक्षित रहे।

जनता हतप्रभ है। बुद्धिजीवी लोकतंत्र में शुचिता को लेकर परेशान हैं। विपक्षी पार्टियां किसी भी कीमत पर शशि थरूर की मंत्री पद से विदाई चाहती हैं। कायदे से शशि थरूर की विदाई तो उसी दिन हो जानी चाहिए थी जिस दिन उनके पंच सितारा होटल में प्रतिदिन एक लाख रूपये खर्च करने की बात बाहर आयी थी। थरूर की विदाई नहीं होगी। उन्होंने माफी मांग ली है। इसलिए कांग्रेस को इस विषय में लीपापोती करने में कठिनाई नहीं होगी। कांग्रेस को मालूम है कि उनके पास प्रचंड बहुमत है। उन्हें पांच साल के लिए शासन करने का अधिकार मिला हुआ है। जनता को सबक सिखाने का मौका तो पांच साल बाद मिलेगा। इस दौरान जनता को शशि थरूर की भेड़–बकरी क्या याद रहेगी? ऐसे भी भारतीय जनता भूलने में विश्वास करती है। नुकसान तो लोकतंत्र का हो रहा है। शशि थरूरों से लोकतंत्र की जड़ें कमजोर होगीं। जनता का विश्वास लोकतंत्र से उठेगा। लोकतंत्र के खिलाफ कई प्रतिक्रियावादी शक्तियां पहले से ही सक्रिय हैं, जिसे हम नक्सली आंदोलन के तौर पर भी देख सकते हैं। ये शक्तियां मजबूत हुईं तो फिर हमारा लोकतंत्र क्या पराभव के रास्ते पर नहीं जायेगा? इसलिए शशि थरूरों से लोकतंत्र को बचाना जरूरी है। क्या कांग्रेस पार्टी यह समझने के लिए तैयार है कि लोकतंत्र में जन प्रतिनिधि का आचरण अनुकरणीय होना चाहिए? बापू की विरासत के साथ यह कैसा खिलवाड़ है? ■

आगामी नगरीय निकायों के चुनाव की चुनौती के लिये बहनें तैयार हों - सुषमा स्वराज

भारतीय जनता पार्टी की वरिष्ठ नेत्री और लोकसभा में प्रतिपक्ष की उपनेता श्री सुषमा स्वराज ने विदिशा संसदीय क्षेत्र के खातेगांव और इच्छावर में महिलाओं के सम्मेलन को संबोधित करते हुए आगामी नगरीय निकायों के चुनाव की चुनौती के लिये कमर कसकर तैयार रहने का आह्वान किया। सम्मेलन की अध्यक्षता, महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष सीमा सिंह ने की। पार्टी की प्रदेश मंत्री सरिता देशपाण्डे ने भी सम्मेलन को संबोधित किया। खातेगांव में सम्मेलन के अवसर पर श्रीमती सुषमा स्वराज ने स्थानीय विकास के लिये समर्पित, पहल स्मारिका का विमोचन किया और इस प्रयास की सराहना की।

श्रीमती सुषमा स्वराज ने कहा कि महिलाएं आंचलिक समस्याओं के प्रति अधिक गंभीर और संवेदनशील रहती हैं। वे नागरिकोचित सुविधाओं के विकास में निर्णायक भूमिका का निर्वाह करेंगी। महिला बहनों की स्थानीय समस्याओं के प्रति जागरूकता और समाधान की पहल ही उनकी स्वीकार्यता का विस्तार करेगी। उन्होंने आशा व्यक्त की कि प्रदेश सरकार की महिला सशक्तिकरण की नीतियां प्रदेश में परवान चढ़ी है। महिलाओं को निकायों में 50 प्रतिशत का आरक्षण मिला है जिससे बहनों की भूमिका बढ़ी है। लोकतंत्र में समान भागीदारी की अगली सीढी चढ़ गयी है। भाजपा बहनों के लिये लोकसभा और विधानसभा में भी 33 प्रतिशत आरक्षण की पक्षधर हैं तथा इसके लिये संसद से सड़क तक संघर्ष जारी रखा जायेगा।

श्री सुषमा स्वराज ने कहा कि इन चुनावों में जीतने वाली महिलाओं का संसदीय क्षेत्र सम्मेलन आयोजित कर विजयी महिलाओं का सम्मान किया जायेगा। आने वाला समय महिला श्रेष्ठता का होगा। ■

पूजा की थाली पर भी महंगाई की मार

महंगाई का असर न सिर्फ दाल–चावल पर ही है बल्कि अब पूजा की थाली और फलाहार की सामग्री पर भी दिखने लगा है। चैत्र नवरात्र से शरदीय नवरात्र यानी छह महीने में ही 15–20 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है। सभी सामग्री में तेजी आई है। इसके पीछे न केवल मांग बढ़ने का कारण है बल्कि पूरे व्यापार में आई तेजी बताई जा रही है। फूल माला की कीमतें दोगुना हो गई हैं। गेंदा फूल की छोटी माला 10 रूपये तो गुलाब के फूलों की माला 50 से 60 रूपये में मिल रही है।

इन दिनों फलाहारी सामग्री के मूल्य में जबरदस्त वृद्धि हुई है। बाजार में पकी पकाई थाली तो महंगी हुई ही है। साथ ही कुट्टु का आटा, सामक का चावल यहां तक कि सेंधा नमक के मूल्य में भी तेजी आई है। इसके साथ ही फलों के मूल्य में भी बेतहाशा वृद्धि हुई है। फलाहार सामग्री के मूल्य में भी वृद्धि हुई है। खुदरा और थोक दोनों व्यापारी महंगाई को कारण बता रहे हैं। सदर बाजार ट्रेडर्स एसो. जनरल सेक्रेटरी देवराज बावेजा मांग और महंगाई को कारण बता रहे हैं तो किराना कमेटी के प्रधान प्रेम अरोड़ा महंगाई और अच्छी फसल नहीं होने को इसका कारण समझते हैं। चैत्र नवरात्र में कुट्टु का चावल जहां 40 रूपये प्रति किलो बिक रहा था वहीं अभी खुदरा व्यापारी 60 रूपये प्रति किलो तक बेच रहे हैं। इसी तरह सामक का चावल 42 रूपये प्रति किलो से बढ़कर पचास रूपये प्रति किलो, तीन सौ रूपये किलो बिकने वाला मखाना 360 रूपये किलो बेचा जा रहा है। मूंगफली के दाने, सामक का चावल, आलू चिप्स, सिंघाड़े का आटा, सेंधा नमक, साबूदाना आदि के मूल्य में भी इजाफा हुआ है। ■

सामग्री	**चैत्र (मार्च)**	**शारदीय (सितंबर)**
कुट्टु आटा	50–55 रूपये	65–70 रूपये
सिंघाड़ा आटा	65–70 रूपये	75–80 रूपये
साबूदाना	45–50 रूपये	50–65 रूपये
आलू चिप्स	70–80 रूपये	65–100 रूपये
मखाना	255–305 रूपये	280–310 रूपये
सामक चावल	45 रूपये	50–55 रूपये
सेंधा नमक	14 रूपये	15 रूपये
पनीर	110–120 रूपये	120–145 रूपये

बदइंतजामी की भेंट चढ़ा छह लाख टन अनाज

केंद्र सरकार एक ओर सादगी का अभियान चला कर पाई–पाई बचाने का दिखावा कर रही है, दूसरी ओर बदइंतजामी के चलते करीब छह लाख टन गेहूं, चावल व अन्य खाद्यान्न खराब हो गया है। केंद्रीय खाद्य एजेंसी भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई) ने एक साल पहले स्वीकार किया था कि दस सालों में उसके गोदामों में पड़ा करीब 13 लाख टन से अधिक खाद्यान्न सड़ चुका है।

अगस्त तक का हाल

केंद्रीय खाद्य व आपूर्ति मंत्रालय के सूत्रों के अनुसार इस वर्ष अब तक एफसीआई का छह लाख टन खाद्यान्न खराब हो चुका है। यह आंकड़ा अगस्त 2009 तक का है। मंत्रालय के अनुसार एफसीआई ने भौतिक सत्यापन के बाद बताया है कि करीब सवा दो लाख टन से अधिक खाद्यान्न अकेले पंजाब में खराब हुआ है। एफसीआई यहां क्षमता से अधिक खरीद करता रहा है। हरियाणा में करीब 64 हजार टन व उत्तरप्रदेश में एक लाख तीस हजार टन गेहूं खराब हुआ है। गेहूं खराब होने की प्रमुख वजह अंकुरण बताया जा रहा है।

धान की बर्बादी

खुले में भंडारण के कारण देशभर में 22 हजार टन से अधिक धान बर्बाद हो चुका है। इस मामले में बिहार व आंध्र प्रदेश आगे हैं। किसी एक गोदाम में सबसे अधिक खाद्यान्न खराब होने का मामला मध्यप्रदेश के महू का है। यहां करीब 17 हजार टन से अधिक अनाज खराब हुआ है। एफसीआई ने हालांकि यह स्पष्ट नहीं किया कि यह आंकड़ा कितने वर्षों का है।

क्या है मूल वजह?

खाद्यान्न खराब होने का मूल कारण क्षमता से अधिक खरीदी है। पिछले साल करीब 530 लाख टन गेहूं–चावल की खरीद हुई थी। जबकि एफसीआई समेत अन्य एजेंसियों के पास मात्र 380 लाख टन की भंडारण क्षमता है। ऐसे में पिछले तीन साल से अनाज का भंडारण खुले में करना पड़ रहा है।

चूहे खा गए १७ हजार टन

खुले में गेहूं व धान के भंडारण के कारण सबसे अधिक मौज चूहों और कीड़ों की है। मंत्रालय की रिपोर्ट के मुताबिक वित्तीय वर्ष 2007–08 व 2008–09 में 17 हजार टन से अधिक खाद्यान्न चूहे या कीड़े मकोड़ों द्वारा चट किए जाने का अनुमान है। ■

साभार : दै. भास्कर

सार्वजनिक जीवन का अवमूल्यन रोका जाना जरूरी : शांता कुमार

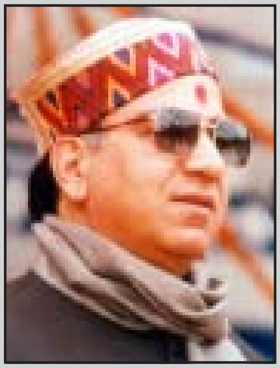

भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष व हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री श्री शांता कुमार ने अपने सफल जीवन के 75 वर्ष पूरे कर लिए हैं। इस अवसर पर 'कमल संदेश' के ''अम्बा चरण वशिष्ठ'' ने उनसे विभिन्न विषयों पर चर्चा की। श्री कुमार ने बताया कि राजनीति में मेरी प्रेरणा देशसेवा की रही है और इन्हीं आदर्शों के अनुसार मैं अपना जीवन जी पाया। उन्होंने चिंता व्यक्त की कि राजनीति और सार्वजनिक जीवन का अवमूल्यन यदि नहीं रोका गया तो देश का भविष्य अंधकारमय हो जाएगा। हम यहां साक्षात्कार के प्रमुख अंश प्रकाशित कर रहे हैं।

आप अपने सफल जीवन के ७५ वर्ष पूरे कर लिए हैं, इस अवसर पर आपके मन में आज क्या लग रहा है?

जीवन के इस लम्बे सफर के इस अंतिम मोड़ पर आकर मुझे परम संतोष का अनुभव हो रहा है। प्रभु कृपा से मैं अपने आदर्शों के अनुसार जीवन जी पाया। सफर की ऊबड़–खाबड़ पगडंडियों और रास्तों में से चलते–चलते यहां तक पहुंचा हूं। ईश्वर ने बहुत कुछ करने का मौका दिया। एक छोटे से गांव में एक साधारण परिवार में जन्म लेकर मैं अपने देश और प्रदेश में पद व प्रतिष्ठा प्राप्त कर जीवन को सफल बना सका। मैं इसके लिए परिवार, समाज और प्रभु का धन्यवादी हूं।

आप छोटी आयु में राजनीति में आ गये। आपको उस समय राजनीति में आने के लिए प्रेरणा कहां से मिली?

स्कूल शिक्षा प्राप्त करते समय राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संपर्क में आया। देश सेवा करने की तीव्र इच्छा पैदा हुई। 10वीं पास करने के बाद प्रचारक के रूप में निकल गया। कुछ समय के बाद भारतीय जनसंघ में काम करने लगा। प्रारम्भ से ही केवल अपने लिए नहीं देश और समाज के लिए कुछ करने की इच्छा रही। उस आयु में वह इच्छा इतनी तीव्र थी कि 19 वर्ष की आयु में 1953 में काश्मीर आंदोलन में सत्याग्रह करके दस महीने मैं जेल में खुशी–खुशी बिता सका। राजनीति में मेरी प्रेरणा देश सेवा की रही है।

राजनीति में आने के आपके क्या आदर्श थे? क्या आप उन्हें प्राप्त कर सके हैं?

सेवा और नैतिक मूल्यों की राजनीति मेरा आदर्श रहा। अपने लम्बे राजनैतिक सफर में मैंने उन आदर्शों को निभाने का प्रयत्न किया है। कई बार जीवन में सत्ता और पद के मुकाबले मैंने आदर्शों को प्राथमिकता दी और उसके लिए मूल्य भी चुकाया है।

अपने राजनीति में रहते हुए भी अपने लेखन कार्य को निभाया। आपकी प्राथमिकता क्या है? क्या पहले राजनेता हैं या लेखक?

पहले और बाद में और अंत में मैं एक देशभक्त हूं। मैंने विभिन्न रूपों में उसी लक्ष्य को पूरा करने की कोशिश की है। राजनीति में रहते हुए भी देश की सेवा नैतिक मूल्यों की रक्षा और दरिद्रनारायण की चिंता करने का प्रयत्न किया। इसीलिए उन उद्देश्यों को पूरा करने के लिए मैंने विभिन्न पदों पर रह कर उस प्रकार की कई योजनाएं प्रारम्भ की। लेखक के रूप में भी मैं उन्हीं आदर्शों को उजागर करने की कोशिश करता रहा। राजनीति की व्यस्तताओं में रहते हुए भी मेरा लेखक जीवित रहा और लेखन कार्य करते हुए भी मेरा राजनेता जागरूक रहा क्योंकि दोनों साधन थे साध्य नहीं थे।

आपने गौरवशाली राजनैतिक जीवन जिया है। एक साधारण कार्यकर्ता से प्रारम्भ करके आप दो बार प्रदेश के मुख्यमंत्री फिर केन्द्र में कैबिनेट मंत्री और फिर अखिल भारतीय उपाध्यक्ष के पद पर पहुंचे। आपको क्या लगता है कि राजनीति में अभी भी आपको कुछ और करना है?

मैंने कभी न किसी पद की याचना की और न ही केवल पद के लिए काम किया। मुझे मेरी पार्टी ने जब जो काम सौंपा मैं उसे करता रहा। मैं तो प्रभु के पास भी कभी भिखारी बन कर नहीं गया, गया तो सिर्फ आभारी बनकर गया। मुझे प्रभु ने और मेरी पार्टी ने बहुत कुछ दिया, मैं उस के लिए धन्यवाद करता हूं। मुझ से और क्या करवाना है, यह निर्णय उन्हीं को करना है। मैंने अब कोई भी चुनाव न लड़ने का निर्णय लिया है। किसी पद प्रतिष्ठा की इच्छा नहीं परन्तु मैं जीवन के अंतिम क्षण तक देश सेवा के लिए संकल्प को पूरा करता रहूंगा।

आपको लगता है कि अभी भी आपको कुछ ऐसा काम करना है

जो आप आज तक नहीं कर सके?

छोटे से जीवन में कोई भी मनुष्य सब कुछ नहीं कर सकता। मैं अपने जीवन में बहुत कुछ कर पाया। ईश्वर ने मुझे कितना कुछ करने में सहयोग दिया। हिमाचल प्रदेश में पीने का पानी, अन्त्योदय, प्रदेश को बिजली की योजनाओं में रॉयल्टी, दिल्ली में रहते हुए स्वजलधारा, हरियाली, करोड़ों अति गरीब लोगों के लिए अन्त्योदय अन्न योजना..... इस प्रकार की बहुत सी योजनाएं प्रारम्भ करने का मौका मिला। राजनीति में नैतिक मूल्यों के लिए लड़ता रहा। भ्रष्टाचार से कभी समझौता नहीं किया और इसके लिए बड़े से बड़ा मूल्य चुकाया। मंत्री पद से मैंने त्यागपत्र भी दिया। मुझे प्रसन्नता है कि मैं अपने आदर्शों की कसौटी पर ठीक उतरता रहा।

आपके जीवन का सबसे गौरवशाली क्षण कौन सा था?

जब भी किसी पद पर बैठने का समय मिला मुझे प्रसन्नता हुई। परन्तु मुझे सबसे गौरवशाली क्षण वह लगता है जब मैंने सिद्धांत और नैतिकता के लिए कुर्सी को छोड़ने की हिम्मत दिखाई। 1980 में जब दल बदल हो रहा था तब मैं भी धन और पद का लालच देकर अपनी सरकार कुछ समय के लिए बचा सकता था। लोग मेरी सहायता के लिए तैयार थे परन्तु मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। मुख्यमंत्री पद से तुरंत त्यागपत्र देकर मैं सीधा शिमला के सिनेमा हाल में सिनेमा देखने चला गया था। मुझे सिनेमा हाल में देखकर कुछ मित्र पास आये और आंसू बहाने लगे थे। तब मैंने उन्हें कहा था कि मैं शान से इस पद पर बैठा था। सेवा और ईमानदारी से काम किया और अब उसी शान से मैंने पद छोड़ दिया। मन में कोई दुख नहीं है इसलिए सिनेमा देख रहा हूं।

आप पिछले ६० वर्षों में राजनीति में हैं उस समय की और आज की राजनीति में क्या अंतर है?

सब कुछ बदल गया। उस समय राजनीति सेवा की थी। भारतीय जनसंघ के रूप में हम लोग केवल देश सेवा की भावना से पार्टी में आये थे आज सोचता हूं 60 साल पहले 19 वर्ष की आयु में मैं जब हिसार जेल में बंद था तो मेरी आंखों में क्या सपने थे। कोई पद प्रतिष्ठा का विचार तक नहीं आता था। देश की सेवा और एक महान भारत बनाने का सपना केवल यही हमारी प्रेरणा थी। आज की राजनीति पूरी तरह पटरी से उतर गई है। राजनीति का अपराधीकरण भी हो गया और व्यापारीकरण भी हो गया। भ्रष्टाचार ने राजनीति को पूरी तरह से भ्रष्ट कर दिया। राजनीति और सार्वजनिक जीवन का अवमूल्यन यदि नहीं रोका गया तो देश का भविष्य अंधकारमय हो जाएगा।

राजनीति का यह अवमूल्यन किस कारण हुआ है?

आजादी की लड़ाई के समय देश में अच्छे स्तर के देशभक्त व ईमानदार नेता थे। उन्हीं का प्रकाश नीचे तक जाता था। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद धीरे–धीरे नेताओं का स्तर गिरता गया। प्रेरणा देने वाले आदर्श नेता कम होते गये। पद और सत्ता ने राजनीति को एक धंधा बना दिया। ऊपर से चलने वाला अवमूल्यन नीचे तक पहुंच गया। राजनीति में उच्च आदर्श वाले प्रखर नेताओं की कमी ही इस अवमूल्यन का कारण है।

आज की राजनीति में क्या सुधार हो सकता है?

असम्भव नहीं है। लेकिन बहुत ही कठिन है। मेरे विचार में आज भी संसदीय प्रणाली भारत के लिए उपयुक्त नहीं। इस प्रणाली में राजनीतिक अस्थिरता और भ्रष्टाचार निहित है। पूरा बुनियादी परिवर्तन करना होगा परन्तु आज के नेताओं का इसी प्रणाली में निहित स्वार्थ हो गया है। परन्तु अब स्थिति इतनी खराब हो गई है कि इस पतन में से ही नव–निर्माण की क्रांति उभरेगी।

आपके जीवन में सबसे अधिक प्रभाव किस का रहा?

गीता और स्वामी विवेकानंद मेरे जीवन का आदर्श रहे हैं।

वर्तमान पीढ़ी को और कार्यकर्ताओं को आप क्या संदेश देंगे?

पिछली पीढ़ी ने अपनी जवानी का रक्त देकर देश को आजाद करवाया था। उस आजादी को संभाल कर रखने की जिम्मेदारी वर्तमान पीढ़ी की है। कोई भी देश छल–कपट और भ्रष्टाचार से कभी महान नहीं बनता। नैतिकता और मूल्यों की राजनीति लाये बिना भारत का उज्ज्वल भविष्य नहीं बनाया जा सकता। 1947 से पहले यदि देश के लिए मर–मिटने की जरूरत थी तो आज देश के लिए पूरी ईमानदारी के साथ काम करने की जरूरत है। ■

श्रद्धांजलि

डा. शीमा रिजवी नहीं रही

उत्तर प्रदेश विधान परिषद की सदस्य और पूर्व में उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री रही भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा की राष्ट्रीय उपाध्यक्षा डा. शीमा रिजवी का 19 अगस्त 2009 को लखनऊ में देहांत हो गया। 11 अगस्त 2009 को दिमागी नस फटने पर उन्हें अस्पताल में भर्ती किया गया था जहां पर उनका आप्रेशन भी किया गया। मगर वह फिर भी बच न सकी।

डा. शीमा रिजवी ने उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी में सक्रिय रूप से कार्य किया वह एक लोकप्रिय वक्ता भी थी। डा. शीमा रिजवी लखनऊ विश्वविद्यालय में उर्दू विभाग की अध्यापक थी और उन्होंने साहित्य में उल्लेखनीय कार्य किये। डा. शीमा रिजवी ने महिलाओं के उत्थान के लिये संघर्षशील कार्य किये। उनके निधन पर भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेतृत्व ने शोक व्यक्त किया है। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री राजनाथ सिंह ने कहा कि उनके निधन से पार्टी को अपूरणीय क्षति हुई है। ■

खुदरा व्यापारियों के हितों की रक्षा पर विशेष ध्यान दिया जाए

हरिद्वार में 5–6 सितम्बर '09 को भाजपा व्यापार प्रकोष्ठ की राष्ट्रीय कार्यकारिणी तथा राज्य के व्यापारी प्रतिनिधियों की बैठक आयोजित हुई। इस बैठक में उत्तराखण्ड के मुख्य मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक, पूर्व मुख्य मंत्री श्री भवनचन्द्र खण्डूरी और श्री भगत सिंह कोश्यारी, नगरविकास मंत्री श्री मदन कौशिक, उत्तराखण्ड भाजपा संगठनमंत्री श्री नरेश बंसल, प्रकोष्ठ संयोजक श्री श्याम बिहारी मिश्रा, सह–संयोजक श्री घनश्याम अग्रवाल समेत राष्ट्रीय तथा 18 प्रदेशों से आए पदाधिकारियों एवं प्रभारियों ने संबोधित किया। बहस में नीचे संक्षेप में वर्णित बातें सामने आई, जिसे गहन विचार विमर्श के बाद निम्नांकित आर्थिक प्रस्ताव पारित किए गयेः–

व्यापारी वर्ग समाज को विभिन्न रुपों में सेवा करता आ रहा है, तथा प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष कर का भुगतान कर राष्ट्र की अर्थव्यवस्था में अपना अमूल्य योगदान देता आया है। इसके बदले आज तक, राष्ट्र से उन्हें कोई सहायता नहीं मिली है, बल्कि लालफीताशाही, इंसपेक्टर राज और अवैधानिक वसूली से व्यापारी वर्ग हमेशा ग्रसित रहा है। देश में लगभग 10 करोड़ व्यापारी हैं जिसमें पटरी व खोखा दुकानदारों की संख्या बहुत अधिक है, और उसके ऊपर कोई भी सरकार ध्यान नहीं दे रही है बल्कि अतिक्रमण के नाम पर बुलडोजर चलाकर उनकी दुकानों व समान को नष्ट कर दिया जाता है। विश्व में खुदरा व्यापार, व्यापार जगत का सबसे बड़ा व्यापारिक क्षेत्र है। इससे देश के करोड़ों व्यापारी,कर्मचारी एवं उन पर आश्रित परिवार का भरण–पोषण होता है। इस क्षेत्र में विदेशी पूंजी निवेश की अनुमति दी गई तो इस क्षेत्र के लाखों व्यापारी बरोजगार हो जाएंगे।

व्यापार प्रकोष्ठ ने व्यापारियों के हित के लिए 12 बिंदुओं वाले आर्थिक प्रस्ताव में सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना, व्यापारी कल्याण कोष की स्थापना, व्यापारी दुर्घटना बीमा की योजना, व्यापारी सुरक्षा आयोग का गठन, व्यापारियों का विधान परिषदों एवं राज्यसभा में प्रतिनिधित्व का प्रावधान और बिक्री कर एवं ऋण प्रणाली में सुधार इत्यादि बातें प्रमुखता से उठाई गई तथा इसको जल्द से जल्द लागू करने कि मांग की गई। विश्व के 22 प्रमुख देशों नें पंजीकृत व्यापारियों के लिए उसकी सेवा निवृत्त होने पर पेंशन का प्रावधान किया है। उत्तर प्रदेश (4 लाख रु.), उत्तराखण्ड (3 लाख रु.) समेत अनेक राज्यों में व्यापारी दुर्घटना बीमा की योजना लागू है जिसे अन्य राज्यों को भी शीध्र ही लागू कर देना चाहिए।

> ***कमरतोड़ महंगाई तथा इस संबन्ध में व्यापारियों को दी गई प्रताड़ना के विरुद्ध 27 अक्टूबर '09 को जंतर–मंतर दिल्ली में विशाल धरना प्रदर्शन का आयोजन***

मुख्य मंत्री श्री निशंक ने राज्य के राजस्व जुटाने में व्यापारियों की अहम भूमिका की चर्चा करते हुए, बैठक में उठाए मुद्दों पर विचार किया तथा तुरन्त व्यापारी दुर्घटना बीमा राशि को बढ़ा कर 5 लाख कर दिया तथा व्यापारियों के सहयोग से उत्तराखण्ड को मॉडल स्टेट बनाने की बात कही।

बैठक में अपने विचार रखते हुए बिहार से राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य सह प. बंगाल प्रभारी वी. के. सिंह ने बढ़ती हुई महंगाई तथा उसे रोकने में अर्थशास्त्री मनमोहन सिंह सरकार की अक्षमत्ता पर सवाल उठाते हुए कहा कि देश की अर्थव्यवस्था बिगड़ी हुई है तथा सभी आर्थिक प्रगति सूचकांक मंदी दर्शा रहे हैं। इसके बावजूद सरकार ने 6.2 जी. ड़ी. पी. का विकास दर दिखलाया है। ऐसा लगता है कि सरकार महंगाई के द्वारा सकल घरेलू उत्पाद में बढोतरी दर्शा रही है जिससे इस कमरतोड़ मंहगाई में राज्य की जनता एवं अर्थव्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है।

इस कमरतोड़ महंगाई तथा इस संबन्ध में व्यापारियों को दी गई प्रताड़ना के विरुद्ध 27 अक्टूबर '09 को राष्ट्रीय कार्यकारिणी व्यापार प्रकोष्ठ नें देश के सारे व्यापारियों को जंतर–मंतर नई दिल्ली पर विशाल प्रर्दशन एवं धरना का आयोजन किया है तथा इसमें सबको सम्मिलित होने का आवाह्न किया। ■

मुख्तार अब्बास नकवी विधानसभा चुनाव प्रबंधन के संयोजक बने

भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री राजनाथ सिंह ने श्री मुख्तार अब्बास नकवी को आगामी विधानसभा चुनावों हेतु प्रबन्धन एवं समन्वय का केंद्रीय संयोजक नियुक्त किया है। श्री नकवी इन राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव में चुनाव प्रबन्धन एवं अन्य विषयों पर प्रदेश इकाइयों से समन्वय करेंगे। महाराष्ट्र, हरियाणा और अरूणाचल प्रदेश में चुनाव हो रहे हैं, जबकि कुछ ही दिनों में झारखण्ड एवं कई अन्य राज्यों में चुनाव होने वाले हैं। ■

स्थायी विकास माडल की आवश्यकता

Hkkरतीय जनता युवा मोर्चा पर्यावरण एवं जल प्रबंधन प्रकोष्ठ द्वारा ''पर्यावरण सरंक्षण : समय की मांग'' विषय पर एक दिवसीय राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन 17 सितम्बर, 2009 कांस्टीट्यूशन क्लब, रफी मार्ग, नई दिल्ली में किया गया।

कार्यशाला का उद्घाटन करते हुए डॉ. मुरली मनोहर जोशी ने कहा कि मनुष्य ने तकनीक को विकास के लिए विकसित करते समय उसके दुष्परिणाम को नहीं सोचा। परिणामस्वरूप तथाकथित विज्ञान के विकास में पर्यावरण को बुरी तरह नष्ट किया। वर्तमान विकास की सोच ने प्रकृति को मनुष्य के उपभोग के पूर्ति का साधन मात्र माना जिसके कारण इसका बुरी तरह से शोषण प्रारंभ किया। परिणाम आज सामने है। भारतीय विचार में प्रकृति को हम संपूर्णता से देखते है, और उसके साथ स्वयं का संबंध जोड़ते हैं। परिणामस्वरूप हवा, पानी, पेड़, पहाड़ ठीक से रहे इसकी चिंता करते हैं। पश्चिम के विकास माडल में इसकी चिंता नहीं की। जिसके कारण आज जल–प्रदूषण, वायु प्रदूषण, ओजोन मंडल में छेद, धरती का बढ़ता तापमान एवं बदलते मौसम के रूप में पर्यावरण का संकट हमें दिख रहा है। इसका संरक्षण भारतीय संस्कृति के अनुरूप जीवन शैली अपनाकर ही किया जा सकता है। डॉ. जोशी ने कहा प्रकृति मनुष्य के आवश्यकताओं की पूर्ति करने में सक्षम है, परन्तु उसके लालच को पूरा नहीं कर सकती। सर्वविदित है कि दुनिया में संसाधन सीमित है; अतः सीमित विकास का माडल ही बनना चाहिए। उन्होंने कार्यशाला में आए युवाओं से आह्वान किया कि वे विकास का ऐसा माडल तैयार करें जिसमें दुनिया विकसित हो और पर्यावरण भी संरक्षित रहे।

उद्घाटन सत्र में युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित ठाकर ने कहा कि हमारी युवा मोर्चा की यह प्रकोष्ठ पर्यावरण के क्षेत्र में कार्य करने को इच्छुक युवकों को एक अवसर प्रदान करेगी ताकि भविष्य में र्प्यावरण संरक्षण में वह अपनी भूमिका सुनिश्चित कर सके। सत्र को

पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता राजीव प्रताप रूढ़ी, युवा मोर्चा के राष्ट्रीय महामंत्री संजीव चौरसिया, विधायक सरयू राय ने भी संबोधित किया। सत्र का संचालन राकेश भास्कर (पर्यावरण एवं जल प्रबंधन प्रकोष्ठ के राष्ट्रीय संयोजक) कार्यशाला के तकनीकी सत्र में देश के प्रसिद्ध पर्यावरण–विद, मनोज मिश्र, ऋतृक दत्ता, संजय कॉल एवं मल्लिका अर्जुन ने अपने–अपने विषय पर अलग–अलग सत्र में पूरे देश से आये युवाओं को पर्यावरण के संरक्षण कैसे किया जाए यह समझाया।

समारोप सत्र में झारखण्ड से आये दामोदर बचाओ आन्दोलन के अध्यक्ष सरयू राय जी ने नदियों में घट रहे जल स्तर के साथ–साथ प्रकृति के शोषण को कैसे रोका जाय इस विषय पर अपने विचार दिये। कार्यशाला में दिल्ली विश्वविद्यालय, इन्द्रप्रस्थ विश्व विद्यालय, जामिया, मानव इंटर नेशनल, अमेटी विश्व विद्यालय के छात्रों ने विशेष रूप से भाग लिया।

इस कार्यशाला का स्वागत भाषण युवा मोर्चा के राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष असीम गोयल, विषय प्रवेश राष्ट्रीय महामंत्री संजीव चौरसिया और धन्यवाद कार्यालय मंत्री संदीप ठाकुर ने किया। मंच संचालन कार्यक्रम संयोजक राकेश भास्कर ने किया। ■

बिशन सिंह चुफाल उत्तराखंड भाजपा के अध्यक्ष बने

भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री राजनाथ सिंह ने श्री बिशन सिंह चुफाल को भाजपा उत्तराखंड प्रदेश का अध्यक्ष मनोनीत किया है। विदित हो कि प्रदेश अध्यक्ष बच्ची सिंह रावत के इस्तीफा देने के बाद श्री चुफाल नये प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। श्री चुफाल पिथौरागढ़ जिले के डीडीहाट विधानसभा क्षेत्र से विधायक हैं। वे प्रदेश में वन परिवहन सहकारित मंत्री के पद पर भी आसीन हैं।

श्री बिशन सिंह चुफाल ने कहा है कि वह पार्टी नेतृत्व की अपेक्षाओं पर खरा उतरने की पूरी कोशिश करेंगे। ■

भाजपा में कार्यकर्ता ही नाभिकुंड

Hkk रतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष नरेन्द्र सिंह तोमर ने कहा कि लोकतंत्र में राजनीति का चेहरा जनोन्मुखी होना चाहिए। इसके लिए राजनैतिक दलों को अपनी जबावदेही खुद तय करनी होगी। उन्होंने कहा कि भाजपा ने संवेदनशील कार्यकर्ता और सक्षम नेतृत्व देने के निहित उद्देश्य से पार्टी में प्रशिक्षण की परिपाटी पर अमल शुरू किया है। प्रशिक्षण की यह प्रक्रिया पार्टी में सबसे नीचे की इकाई से शुरू की गयी है ताकि विचारधारा के प्रति अंतिम छोर का कार्यकर्ता भी पूरी मजबूती के साथ समाज में सक्रिय रहे। उन्होंने कांग्रेस पर आरोप लगाया कि कांग्रेस सिर्फ सत्ता के उपभोग और चुनाव लडने का एक सिस्टम मात्र है वहां लोकतंत्र और राजनीति दोनों के मायने सत्ता और संसाधनों का उपभोग है, विचारधारा और सामाजिक सरोकारों से उसका कोई नाता नहीं है। भाजपा लोकतंत्र के प्रति अपनी जवाबदेही बखूबी समझती है। श्री तोमर ग्वालियर महानगर के दो दिवसीय प्रशिक्षण शिविर के उद्घाटन सत्र को जीआईटीएस कॉलेज में संबोधित कर रहे थे।

द्वितीय सत्र मूल्य आधारित राजनीति की स्थापना में पदाधिकारियों व जनप्रतिनिधियों की भूमिका पर बोलते हुये भाजपा के वरिष्ठ नेता श्री शीतला सहाय ने कहा कि भाजपा निष्ठा आधारित दल है उसका जन्म और विकास सत्ता प्राप्ति के लिये बल्कि समाज में सार्थक परिवर्तन के लिये हुआ। सार्वजनिक जीवन में मूल्य आधारित राजनीति पार्टी का दर्शन रहा है। डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी और पं. दीनदयाल उपाध्याय के जीवन मूल्य पार्टी का संविधान है और आज के दौर में इस तरह के प्रशिक्षण शिविर पार्टी में काडर को वैचारिक तौर पर मजबूत बनाने का काम करते है।

इस अवसर पर वर्ग का संचालन जिला महामंत्री अरूण कुलश्रेष्ठ ने किया। मंच पर भाजपा प्रदेशाध्यक्ष नरेन्द्र सिंह तोमर, प्रदेश सहसंगठन महामंत्री भगवत शरण माथुर, सांसद मायासिंह, सांसद यशोधरा राजे सिंधिया, मंत्री नारायण सिंह कुशवाह, भाजपा जिलाध्यक्ष अभय चौधरी उपस्थित थे।

इससे पूर्व भाजपा प्रदेशाध्यक्ष नरेन्द्र सिंह तोमर ने दीप प्रज्वलित कर एवं डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी, पं. दीनदयाल उपाध्याय एवं स्व. राजमाता सिंधिया के चित्रों पर माल्यार्पण किया। कैंसर चिकित्सालय की छात्राओं ने वंदे मातरम् गीत का गायन किया। इस अवसर पर वर्ग गीत चैरेवैति चैरेवैति यही तो मंत्र है अपना का गायन भाजपा जिला उपाध्यक्ष मोहन विटवेकन ने किया।

इसके बाद एक अन्य सत्र में भाजपा के प्रदेश सहसंगठन महामंत्री भगवत शरण माथुर ने चर्चा सत्र में भाग लिया एवं इसमें कार्यकर्ताओं एवं उपस्थित पदाधिकारियों की जिज्ञासा का समाधान किया। दिन के अंतिम सत्र में सरकारी दल के नाते कार्यकर्ताओं की भूमिका पर भाजपा के प्रदेश मंत्री एवं विधायक अरविन्द भदौरिया ने अपने विचार उपस्थित पदाधिकारियों के बीच रखे।

भाजपा महानगर के दो दिवसीय प्रशिक्षण वर्ग के समापन सत्र को संबोधित करते हुये भाजपा के प्रदेश महामंत्री संगठन माखन सिंह ने कहा कि जिस प्रकार सेना में सच्चा सिपाही होना सर्वाधिक सम्मानीय है उसी प्रकार भारतीय जनता पार्टी में सर्वाधिक सम्मान का शब्द कार्यकर्ता है। उन्होंने कहा कि हम सब पार्टी के अग्र श्रेणी के कार्यकर्ता है। हम सब के मन में यह भाव होना चाहिए कि हम अपने व्यवहार, आचरण एवं बोलचाल से समाज में ऐसी लाइन खींचे जिस पर चलने में व्यक्ति गौरवन्वित महसूस करें। उन्होंने कहा कि सत्ता की राहें बड़ी रपटीली होती हैं। इसलिये वैचारिक और व्यावहारिक दृष्टि से अपने व्यक्तित्व को मजबूत करने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि भाजपा देश में एक मात्र ऐसा राजनीतिक दल है जहां पार्टी के छोटे छोटे कार्यकर्ता को अपनी बात कहने का अधिकार प्राप्त है। भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता आधारित पार्टी है। लाखों कार्यकर्ता ही पार्टी संगठन के प्राण तत्व है। कार्यकर्ता ही नाभिकुंड है। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी का लक्ष्य देश को दुनिया का सर्वश्रेष्ठ राष्ट्र बनाना है और बिना कार्यकर्ताओं के पार्टी कुछ प्राप्त नहीं कर सकती। हमारे व्यवहार का पार्टी पर और पार्टी के कार्यक्रमों का कार्यकर्ताओं पर असर परिलक्षित होना चाहिये।

इस अवसर पर मंच पर माखन सिंह चौहान, अभय चौधरी, महापौर विवेक शेजवलकर, मंत्री नारायण सिंह कुशवाह उपस्थित थे।

दिन के द्वितीय सत्र को शासकीय योजनाओं में कार्यकर्ताओं की भूमिका विषय पर प्रकाश डालते हुये राज्यसभा सांसद श्रीमती माया सिंह ने कहा कि वर्तमान परिदृश्य में राजनैतिक क्षेत्र में प्रशिक्षण की महती आवश्यकता है और भारतीय जनता पार्टी प्रारंभ काल से ही निरन्तर कार्यकर्ताओं को कार्य क्षेत्र में मजबूती से कार्य करने के लिए प्रशिक्षण वर्ग आयोजित करती रही है। साथ ही उन्होंने कार्यकर्ता किसी भी पद को छोटा न मानकर वरन उसकी भूमिका को समझाने का प्रयास करे। प्रत्येक जनकल्याणकारी योजनाओं की जानकारियां का अध्ययन कर जनता को लाभ दिलाने का हर संभव प्रयास करें। ■

भाजपा ने की विधानसभा चुनाव कराने की मांग

>kरखण्ड विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीति गरमाती जा रही है। सदन की सदस्यता से इस्तीफा देने के बाद भाजपा विधायकों ने चुनाव की मांग को लेकर अब चुनाव आयोग का दरवाजा खटखटाया है। कानून व्यवस्था एवं विकास का मुद्दा उछाल कर भाजपा ने निर्वाचन आयोग से तत्काल चुनाव कराने की मांग की है।

पार्टी के वरिष्ठ नेता श्री यशवन्त सिन्हा के नेतृत्व में विधायकों के प्रतिनिधिमंडल ने चुनाव आयुक्त एस.वाई. कुरैशी से भेंट की। बाद में श्री सिन्हा ने संवाददाताओं को बताया कि प्रतिनिधिमंडल ने आयोग से कहा है कि विधानसभा के कार्यकाल की अवधि समाप्त होने से छह महीने पहले ही चुनाव कराना उसके अधिकार क्षेत्र में है, इसलिए झारखण्ड विधानसभा के चुनाव तुरन्त कराए जाएं। झारखण्ड विधानसभा का कार्यकाल अगले साल 10 मार्च को पूरा हो रहा है। प्रतिनिधिमंडल ने आयोग से कहा कि राज्य में राष्ट्रपति शासन की मियाद 18 जनवरी को समाप्त हो रही है। ऐसे में आयोग वहां चुनाव कराने की प्रक्रिया अभी शुरू कर सकता है।

उन्होंने कहा कि 81 सदस्यीय झारखण्ड विधानसभा के सभी 21 भाजपा विधायकों द्वारा इस्तीफा दे दिए जाने से उसकी वर्तमान सदस्यता इतनी कम हो गई है कि किसी सरकार का गठन सम्भव नहीं है। भाजपा के अलावा एक मनोनीत सदस्य ने भी इस्तीफा दे दिया है। श्री सिन्हा ने कहा कि जब सभी दल संकेत दे चुके हैं कि वहां सरकार बनाने में किसी की रूचि नहीं है तो फिर राष्ट्रपति शासन बनाए रखने और चुनाव नहीं कराने का कोई मतलब नहीं है। उन्होंने कहा कि गृह मंत्री पी. चिदम्बरम लोकसभा में कह चुके हैं कि पार्टी झारखण्ड की वर्तमान विधानसभा में सरकार बनाने की इच्छुक नहीं है। उन्होंने कहा कि इन परिस्थितियों में वहां चुनाव कराना ही एकमात्र विकल्प बचता है और इसमें अब किसी तरह का विलम्ब ठीक नहीं है। ■

दिल्ली

महंगाई की मार से दिल्लीवासियों में हाहाकार

fnल्ली प्रदेश भाजपा ने कांग्रेस के नेतृत्व वाली यूपीए सरकार के शासन में प्रारम्भिक सौ दिनों को 'मंहगाई के सौ दिनों' की संज्ञा दी है। दिल्ली प्रदेश भाजपा की कार्यकारिणी, जिला अध्यक्षों, मंडल अध्यक्षों, विधायकों और पार्षदों की संयुक्त बैठक में प्रस्ताव पारित कर भाजपा ने मंहगाई पर लगाम लगाने में यूपीए सरकार के कार्य प्रदर्शन को घोर निराशाजनक बताया है। बैठक की अध्यक्षता प्रदेश भाजपाध्यक्ष प्रो. ओम प्रकाश कोहली ने की।

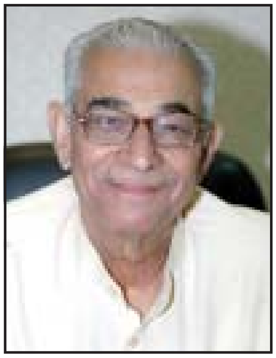

प्रस्ताव में कहा गया है कि आम आदमी की बढ़ चढ़कर दुहाई देने वाली कांग्रेस के शासनकाल में आम आदमी ही महंगाई की सबसे ज्यादा मार झेल रहा है। अनाज, दालें, दूध, चीनी, खाद्य तेल, सब्जियां आम आदमी की पहुंच से बाहर हो गई हैं। इस पर तुर्रा यह कि यूपीए सरकार महंगाई दर में कमी के झूठे आंकड़े पेश कर लोगों को भ्रमित कर रही है। प्रस्ताव में कहा गया है कि रोजमर्रा की आवश्यक वस्तुओं की आसमान छू रही कीमतों को थोक सूचकांक प्रतिबिम्बित नहीं करता। उपभोक्ता सूचकांक आम आदमी के उपयोग की चीजों की कीमतों को दर्शाने वाला अपेक्षाकृत अधिक विश्वसनीय आधार हो सकता है।

प्रस्ताव में दिल्ली सरकार द्वारा महंगाई पर अंकुश लगाने के लिए हाल ही में किए गए उपायों को महज नौटंकी बताया गया है। प्रस्ताव में कहा गया है कि दिल्ली की मुख्यमंत्री ने पहले 80 दुकानों के जरिए सस्ती दाल बेचने की घोषणा की और बाद में मदर डेयरी डिपो के माध्यम से। पर यह योजना मज़ाक बन कर रह गई।

प्रस्ताव में दिल्ली सरकार द्वारा बिजली पर से सब्सिडी खत्म करने और उपभोक्ताओं पर बिजली के बढ़े हुए बिलों का भारी बोझ लादने के लिए दिल्ली सरकार की कड़ी भर्त्सना की गई और बिजली पर सब्सिडी बहाल करने की मांग की गई है। प्रस्ताव में कहा गया है कि बिजली के दोषपूर्ण बिलों ने उपभोक्ताओं की परेशानी और अधिक बढ़ा दी है। हाल ही में मुख्यमंत्री ने बिजली कम्पनियों को जो फटकार लगाई है, वह बिजली कम्पनियों के निराशाजनक कार्य प्रदर्शन की ही स्वीकृति है।■

दिल्ली नगर निगम की स्वायत्तता समाप्ति कतई बर्दाश्त नहीं : भाजपा

भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता तथा संसद सदस्य श्री रवि शंकर प्रसाद द्वारा जारी 14 सितम्बर, 2009 को प्रेस वक्तव्य

fnल्ली नगर निगम को दिल्ली सरकार के नियंत्रण में लाने के केन्द्र सरकार के नापाक इरादे के पीछे उसकी अक्तूबर 2010 में आयोजित होने वाले कॉमनवेल्थ खेलों को सम्पन्न कराने और उनके लिए अपेक्षित बुनियादी ढांचा तैयार करने में बरती गई घोर लापरवाही और निराशाजनक विफलता को छिपाने की चाल है। अब, कॉमनवेल्थ खेलों की फेडरेशन के अध्यक्ष मि. माइकिल फैनल ने भी खेलों की तैयारी में होने वाली धीमी प्रगति के बारे में गम्भीर चिंता व्यक्त की है तथा इसमें गति लाने के लिए प्रधानमंत्री के हस्तक्षेप की मांग की है। वस्तुतः, ऐसी गम्भीर चिंता पहली बार व्यक्त नहीं की गई है। विगत में भी दिल्ली सरकार सहित कॉमनवेल्थ खेल संगठन समिति की संसदीय समिति, महालेखापरीक्षक तथा नियंत्रक जैसे निकायों द्वारा और यहां तक कि खेल मंत्रालय द्वारा घोर आलोचना की गई है। खेल सम्बंधी परियोजनाओं की धीमी प्रगति स्वयं सरकार की विफलता की कहानी कहती है। फ्लाईओवरों तथा पुलों की 35 परियोजनाओं में से केवल 4 पूरी हुई हैं, 6 पर काम शुरू नहीं हुआ हैं और शेष बची 24 परियोजनाओं का समय पर पूरा होना बेहद दूर की कौड़ी हैं। 19 स्टेडियमों में से 11 में लगभग 25–75 प्रतिशत कार्य अभी पूरा होना हैं। इनमें जवाहर लाल नेहरू स्टेडियम शामिल है, जहां पर उद्घाटन और समापन समारोह आयोजित होना हैं। इस स्टेडियम में केवल 50 प्रतिशत कार्य ही पूरा हुआ है। यह ध्यान देने योग्य बात है कि बिजली, पानी, सीवर और परिवहन सीधे दिल्ली सरकार के अधीन आते हैं। यद्यपि अधिकांश सड़कें दिल्ली नगर निगम के अधीन हैं जिनके लिए सरकार ने पैसा मंजूर किए जाने में अड़चन डालने का हरसम्भव प्रयास किया है। उदाहरणार्थ, दिल्ली में 16,826 कि0मी0 सड़कें दिल्ली नगर निगम के अधीन हैं जबकि 2350 कि0मी0 सड़कों का अनुरक्षण दिल्ली सरकार के अधीन लोक निर्माण विभाग द्वारा किया जाता है। महालेखापरीक्षक तथा नियंत्रक की रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2007–08 के लिए जहां लोक निर्माण विभाग को 620 करोड़ रूपये दिए गए वहीं दिल्ली नगर निगम को केवल 170 करोड़ रूपये आबंटित किए गए। इसी प्रकार वर्ष 2008–09 के लिए दिल्ली नगर निगम को केवल 125 करोड़ रूपये दिए गए जबकि लोक निर्माण विभाग की सड़कों के लिए 915 करोड़ रूपये आबंटित किए गए। इससे अधिक खुला दोहरा मानदण्ड कुछ नहीं हो सकता। फिर भी, भाजपा–नीत दिल्ली नगर निगम ने कांग्रेस–नीत दिल्ली नगर निगम की तुलना में सम्पत्ति कर संग्रह में भारी वृद्धि की हैं। कांग्रेस सरकार ने जानबूझ कर धन देने में अटकाए गए अड़ंगों के बावजूद भाजपा–नीत दिल्ली नगर निगम ने अच्छा प्रदर्शन किया है।

> *इसके पीछे एक दूरस्थ राजनैतिक कोण है क्योंकि दिल्ली नगर निगम पर भाजपा का नियंत्रण है। मुख्य प्रश्न यह रह जाता है कि केवल दिल्ली नगर निगम ही क्यों ? नई दिल्ली नगर पालिका, डीडीए (दिल्ली विकास प्राधिकरण) और पुलिस आदि क्यों नहीं, जिन पर भारत सरकार का प्रत्यक्ष नियंत्रण है।*

कार्य के सुचारू निष्पादन के लिए समन्वय का कोई भी प्रयास स्वागत योग्य होता है, किंतु दिल्ली नगर निगम जैसे कानूनी निकाय, जिसको सांविधानिक, संस्वीकृति और स्वायत्तता हासिल है उसको एक विभाग की तरह दिल्ली सरकार के अधीन कर देना पूरी तरह अस्वीकार्य है। केन्द्र सरकार को ध्यान में रखना चाहिए कि नगर निगम अधिनियम के अधीन निगम को निरीक्षण, रिकार्ड की प्रस्तुति तथा अनुपालन हेतु निर्देश देने के कतिपय अधिकार प्राप्त हैं। ये अधिकार सीमित तथा सशर्त हैं, जिन्हें प्रत्यायोजित किया जा सकता है। किंतु, इन अधिकारों के आवरण में दिल्ली नगर निगम की स्वायत्तता को समाप्त नहीं किया जा सकता है और न ही इसे दिल्ली सरकार का विभाग बनाया जा सकता है। स्पष्टतः इसके पीछे एक दूरस्थ राजनैतिक कोण है क्योंकि दिल्ली नगर निगम पर भाजपा का नियंत्रण है। मुख्य प्रश्न यह रह जाता है कि केवल दिल्ली नगर निगम ही क्यों ? नई दिल्ली नगर पालिका, डीडीए (दिल्ली विकास प्राधिकरण) और पुलिस आदि क्यों नहीं, जिन पर भारत सरकार का प्रत्यक्ष नियंत्रण है। भाजपा–नीत दिल्ली नगर निगम को राजनैतिक उद्देश्यों से अधिकार में लेने का पुरजोर विरोध किया जाएगा। ■

आयुर्वेद की बड़ी कार्य योजना बनाकर काम करने की जरूरत : डा. रमन सिंह

vk युर्वेदिक डॉक्टर के रूप में अपने सार्वजनिक जीवन की शुरूआत करते हुए पहले जनादेश से पार्षद बनकर अपने नगर और अब मुख्यमंत्री के रूप में प्रदेश के विकास की बागडोर संभाल रहे डॉ. रमन सिंह का आज दोपहर यहां उनके सहपाठी चिकित्सकों और आयुर्वेद अधिकारियों ने आत्मीय अभिनंदन किया। राज्य में आयुर्वेद चिकित्सा को बढ़ावा देने और आयुर्वेदिक डॉक्टरों की वर्षों पुरानी विभिन्न मांगों को पूर्ण करने पर उनके सम्मान में छत्तीसगढ़ आयुर्वेद अधिकारी संघ ने अपने एक दिवसीय राज्य सम्मेलन में अभिनंदन समारोह का आयोजन किया। समारोह के बाद मुख्यमंत्री ने मंच से नीचे आकर अपने सहपाठी डॉक्टरों सहित सम्मेलन में आए आयुर्वेद चिकित्सकों से बड़ी गर्मजोशी से हाथ मिलाकर सौजन्य मुलाकात की।

मुख्यमंत्री ने राज्य में आयुर्वेद को बढ़ावा देने के लिए एक बड़ी कार्य योजना बना कर काम करने की जरूरत पर विशेष रूप से बल दिया। उन्होंने कहा कि बस्तर से लेकर सरगुजा तक प्रदेश के जंगलों में जड़ीबूटियों से संबंधित पेड़–पौधों की भरमार है। सिर्फ उन्हें पहचान कर उनका बेहतर उपयोग करने की जरूरत है।

मुख्य अतिथि की आसंदी से सम्मेलन को सम्बोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि अधिकारी के रूप में आयुर्वेद चिकित्सक सरकारी नौकरी में है, जिनकी सेवा शर्तों में सुधार आदि की प्रक्रिया तो चलती रहती है, लेकिन उन्हें एक आयुर्वेदिक डॉक्टर के रूप में मरीजों के इलाज के साथ–साथ अपने ज्ञान और अनुभव का उपयोग आयुर्वेद के विकास और विस्तार के लिए भी करते रहना चाहिए। मुख्यमंत्री ने राज्य में आयुर्वेद को बढ़ावा देने के लिए एक बड़ी कार्य योजना बना कर काम करने की जरूरत पर विशेष रूप से बल दिया। उन्होंने कहा कि बस्तर से लेकर सरगुजा तक प्रदेश के जंगलों में जड़ीबूटियों से संबंधित पेड़–पौधों की भरमार है। सिर्फ उन्हें पहचान कर उनका बेहतर उपयोग करने की जरूरत है। मुख्यमंत्री ने इसके लिए आयुर्वेद अधिकारियों से इस प्रकार का एक वृहद प्रोजेक्ट लेकर आगे आने का आहवान करते हुए कहा कि यदि ऐसा कोई बड़ा प्रोजेक्ट राज्य शासन को मिल तो उसके क्रियान्वयन के लिए भरपूर सहयोग भी दिया जाएगा।

उन्होंने कहा कि इस प्रोजेक्ट में आयुर्वेदिक महत्व के वृक्षारोपण को भी शामिल किया जा सकता है। इसके क्रियान्वयन में सरकार आयुर्वेद अधिकारियों, सेवानिवृत्त आयुर्वेद चिकित्सकों और इस क्षेत्र से जुड़े अनुभवी विशेषज्ञों की सेवाएं सलाहकार और मार्गदर्शक के रूप में जरूर लेना चाहेगी।

कार्यक्रम की अध्यक्षता प्रदेश के पर्यटन और संस्कृति मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने की। गुरू तेगबहादुर सभा गृह में आयोजित इस कार्यक्रम स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग के संसदीय सचिव महेशा गागड़ा तथा पद्मश्री सम्मान प्राप्त स्वतंत्रता संग्राम सेनानी और आयुर्वेद चिकित्सक डॉ. महादेव प्रसाद पाण्डे सहित डॉ. व्यासनारायण द्विवेदी और डॉ. रामेन्द्र नारायण शुक्ल विशेष अतिथि के रूप में उपस्थित थे। प्रदेश भर से आए आयुर्वेद अधिकारियों और आयुर्वेद चिकित्सकों को सम्बोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने सभी लोगों को शारदीय नवरात्रि और ईद की बधाई और शुभकामनाएं दी।

डॉ. रमन सिंह ने कहा कि आयुर्वेदिक फार्मेसी और भारतीय चिकित्सा प्रणालियों में रोजगार की काफी संभावनाएं है। उन्होंने कहा कि केन्द्र सरकार ने भारतीय चिकित्या पद्धति का एकीकरण करते हुए एक समन्वित प्रणाली के रूप में उन्हें एलोपैथिक अस्पतालों के साथ जोड़ने का निर्णय लिया है, ताकि मरीजों को अपना ईलाज कराने के लिए हर प्रकार का विकल्प आसानी से मिल सके। छत्तीसगढ़ सरकार ने भी राज्य के एलोपैथिक अस्पतालों में आयुष विंग की स्थापना का कए सिलसिला प्रारंभ किया है। पंचकर्म की सुविधा भी उपलब्ध करायी जा रही है। डॉ. सिंह ने कहा कि राज्य में बनने वाली आयुर्वेदिक औषधियों के लिए एक निश्चित मानक निर्धारित करने की जरूरत है। इसके लिए राजधानी रायपुर के शासकीय आयुर्वेद महाविद्यालय में ड्रग टेस्टिंग लेब की स्थापना की जा चुकी है। उपकरण भी आ चुके हैं, जिनका इस्तेमाल जल्द शुरू होना चाहिए। ■

दीनदयाल उपाध्याय : विनम्र नेतृत्व का आदर्श

i- दीनदयालजी के जीवन का एक प्रसंग भी याद आता है। मैं जब जनसंघ में काम करता था, उस समय एक कार्यकर्ता को चुनाव में उम्मीदवारी न मिलने के कारण वह बहुत ही गरम होकर मेरे पास आया और जोरजोर से कहने लगा– 'मैं पार्टी के लिए बर्बाद हो गया हूं और पार्टी को तो कार्यकर्ता की कद्र ही नहीं।' मैंने उसको पं. दीनदयालजी से मिलने के लिए भेजा। वह बड़े गुस्से में ही था। लेकिन पंडितजी से मिलने दिल्ली गया। पंडितजी ने पूछताछ की और बोले शाम को आराम से खाना वगैरह होने के बाद बातें करेंगे। उन्होंने मान लिया और यह कार्यकर्ता कार्यालय में ही ठहरा। और फिर दिन भर देखता रहा कि पार्टी के ऑल इंडिया जनरल सेक्रेटरी (पंडितजी) दिनभर क्या कर रहे थे। तो कोई खोया हुआ कागज ढूंढने के लिए कचरे की टोकरी में से एक एक कागज देख रहे थे। सायक्लोस्टाईल मशीन हथौड़े से दुरुस्त कर रहे थे। ऐसे मामूली से काम वे कर रहे थे। श्री जगदीश प्रसाद माथुर ने उस कार्यकर्ता को दोपहर का खाना होटल में से खाकर आने को कहा। लेकिन स्वयं पंडितजी ने तो खाना भी नहीं खाया था। दूध और ब्रेड मंगाया था। यह कार्यकर्ता ये सब बातें देख रहा था। उसे लगा कि इस जनरल सेक्रेटरी को बिलकुल प्रतिष्ठा का भाव नहीं है। फिर उसने किसी से पूछा कि पंडितजी कौन से चुनाव क्षेत्र से खड़े हैं? तो जवाब आया, 'अरे, भाई, पंडितजी कहां चुनाव लड़ते हैं?' तो उसने पूछा, 'फिर काम किसका कर रहे हैं?' तो बताया गया कि वे तो तीन सौ लोगों के चुनावी काम में लगे हैं।'

अब शाम छः बजे काम पूरा होने के बाद पंडितजी इस कार्यकर्ता से बात करने के लिए हाथ पैर धोकर तैयार हो गए, दोनों के लिए खाना मंगवाया और बोले, 'अब आराम से अपनी बात बोलो। सवेरे छः बजे तक मुझे अब समय है।' अब ये कार्यकर्ता क्या बोलता? बोला, 'कुछ भी नहीं पंडितजी। मैं आप के दर्शन के लिए आया था।' और फिर ऐसे ही नागपुर चला आया।

अब नागपुर आने के बाद मुझे मिला। मैंने पूछा, भाई आप की शिकायत का फैसला क्या हुआ? वह 'अं। अं। कुछ नहीं, कुछ नहीं करने लगा। मैंने उसे फिर डांटा कि, 'भई, तू बड़े जोर से उस दिन कार्यकर्ताओं के सामने पार्टी की बदनामी कर रहा था तो पंडितजी के सामने अपनी शिकायत क्यों नहीं की?' वह बोला, 'मुझसे गलती हुई। मुझे इस तरह का बर्ताव करना नहीं चाहिए था। मैं तो शिकायत करने ही गया था। लेकिन दिनभर में पंडितजी के बारे में जो देख रहा था, उससे मुझे ऐसा लगा कि इस महापुरूष को मैं कैसे बताऊं कि मैं बर्बाद हो गया।' और आगे बोला, 'मुझे एक शेर याद आ रहा है।

शिकवा क्या करता इस महफिल में कुछ ऐसे भी थे
उम्रभर अपनी जख्मों पर जो नमक छिड़काएं।

संपूर्ण जीवनभर अपने स्वयं के जख्मों पर जो नमक छिड़का रहे हैं ऐसे लोग जब मैंने देखे तो मैं कैसे कहूं कि मेरी उंगली को जरा सी चोट लगी है?■

(यह संस्मरण श्रद्धेय दत्तोपंत ठेंगड़ी द्वारा लिखित पुस्तक ''कार्यकर्ता'' से लिया गया है।)

महाराष्ट्र

विदर्भ में 668 किसानों ने दी जान

e हाराष्ट्र के विदर्भ क्षेत्र में गहराते कृषि संकट के बीच एक दिन के दौरान सात किसानों ने आत्महत्या की है। इसके साथ ही राज्य में आत्महत्या करने वाले किसानों की संख्या बढ़कर 668 हो गई है। राज्य में पिछले पांच वर्षों में आत्महत्या करने वालों किसानों की संख्या सात हजार से अधिक हो गई है।

विदर्भ में किसानों की समस्या के समाधान के लिए संघर्षरत विदर्भ जन आंदोलन समिति के अध्यक्ष किशोर तिवारी ने दावा किया है 24 घंटों के दौरान विदर्भ क्षेत्र में संतोष थेटे (अमरावती), बालाजी मडावी (यवतमाल) गजानन गावंडे (अकोला) विनायक तिजारे (अमरावती), राजेश गुडवार (वाशिम) गजानन लोखंडे (वाशिम) संतोष सिडाम (यवतमाल) नामक किसानों ने आत्महत्या की। उन्होंने एक प्रेस विज्ञप्ति में कहा कि विदर्भ के छह जिलों के लिए 3750 करोड़ रूपये का पैकेज घोषित किया गया है। इनमें यवतमाल में 1596, अमरावती में 1122, अकोला में 1016, वाशिम में 816, बुलढाना में 1077 और वर्धा में 495 किसानों ने आत्महत्या की है। आत्महत्या करने वाले किसानों में अधिकतर बीटी कपास की फसल लेते है लेकिन यह काफी महंगी होने तथा कपास को बाजार में उचित दाम नहीं मिलने के कारण किसानों पर अत्यधिक कर्ज का बोझ बढ़ा रही है जिसके कारण वे आत्महत्या कर रहे हैं।

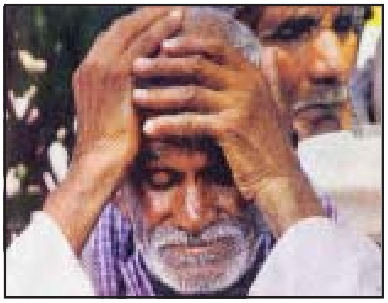

तिवारी ने सरकार ने इन निराश किसानों के लिए स्वास्थ्य सेवा, मुफ्त खाद्यान्न सुरक्षा, उच्च शिक्षा में 100 प्रतिशत रियायत देने की मांग की है।■

(साभार : हिन्दुस्तान)

उदात्त व्यक्तित्व के धनी थे दीनदयालजी

fot; dekj xlr

परम श्रद्धेय दीनदयालजी उपाध्याय का जब कभी स्मरण होता है–हृदय गुदगुदा उठता है। मन विहंस उठता है। क्या जीवन था– क्या सौम्य था– क्या सादगी थी मानो गंगा, यमुना, सरस्वती की त्रिवेणी में गोते लगाकर मन पवित्र एवं निर्मल हो गया हो। अल्प आयु में उनसे मिलना हुआ और वे मुझे प्यार से मुन्ना कहर बुलाते तो हृदय रोमांचित हो उठता। वास्तव में आज भी उनकी स्मृति उन जैसा बनने की प्रेरणा देती है। स्मृति के रूप में कुछ कण उनके जन्म दिवस अर्थात् 25 सितम्बर को प्रस्तुत करने के लिए मन लालायित हो रहा हैः

श्रद्धेय दीनदयाल जी जब उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रचारक थे तब श्री गुरूजी प्रचारकों की बैठक ले रहे थे। गुरूजी ने पूछा यदि आपको बाहर जाने के लिए कहा जाए तो तैयारी में कितना समय लगाओगे। किसी ने कहा एक घंटा, किसी ने कहा आधा घंटा। जब दीनदयालजी से पूछा कि आप बताओ। दीनदयाल जी ने कहा कि समय क्या लगाना– थैला पास है, आप बताएं, उठकर चल पडूंगा।

जब उन्हें संघ कार्य से मुक्त कर राजनीति में लगाया गया तो स्तुति योग्य परम श्रद्धेय डॉ. श्यामा प्रसाद मुकर्जी ने उनके कृतित्व को पहचान कर सरसंघचालक पूज्य गुरूजी से कहा कि ऐसे दो दीनदयाल मुझे और दे दो तो मैं देश का भाग्य बदल दूंगा। इसके बावजूद दीनदयाल जी ने श्री गुरूजी से कहा कि मेरा मन नहीं लगता। श्री गुरूजी ने उनसे कहा कि जिस दिन मन लग जायेगा उसी दिन वापस बुला लेंगे।

एक बार मैं उनके साथ नैनीताल जा रहा था। रास्ते में उन्होंने एक यात्री से कहा जरा अपना ट्रांजिस्टर चला दीजिए। उस यात्री ने सहज ही कहा कि ट्रांजिस्टर तो आपके पास भी है। उन्होंने कहा कि आपके ट्रांजिस्टर पर समाचार सुन लूं तो फिर बताऊंगा कि अपना क्यों नहीं चला रहा हूं। समाचार सुनने के बाद उस यात्री ने पुनः जिज्ञासा से पूछा कि आपने अपना ट्रांजिस्टर क्यों नहीं चलाया? दीनदयाल जी का सहज उत्तर था कि मैंने ट्रांजिस्टर का लाइसेंस अभी तक बनवाया नहीं है और तब तक उसे चलाने का मुझे कोई अधिकार नहीं है। वह यात्री भाव–विभोर हो गया।

एक बार बरेली के एक कार्यक्रम में अति व्यस्त थे। अचानक मुझे बुलाया और कहा कि शाखा पर पूछो कि प्रार्थना कितने बजे करेंगे। मैं दौड़कर गया और पूछकर आया कि प्रार्थना ठीक कितने बजे करेंगे। समय पूछ कर मैंने उन्हें बताया और प्रार्थना से चंद मिनट पहले उठे और प्रार्थना करके कार्यक्रम में व्यस्त हो गए। उनके शब्दों में ''नमस्ते सदा वत्सले.....'' अपनी प्रार्थना एक तंत्र है और इसी के माध्यम से अपने राष्ट्र की दुरव्यवस्था दूर होकर पुनः यह विश्वगुरू के रूप में प्रस्थापित होगा।

> *जब उन्हें संघ कार्य से मुक्त कर राजनीति में लगाया गया तो स्तुति योग्य परम श्रद्धेय डॉ. श्यामा प्रसाद मुकर्जी ने उनके कृतित्व को पहचान कर सरसंघचालक पूज्य गुरूजी से कहा कि ऐसे दो दीनदयाल मुझे और दे दो तो मैं देश का भाग्य बदल दूंगा। इसके बावजूद दीनदयाल जी ने श्री गुरूजी से कहा कि मेरा मन नहीं लगता। श्री गुरूजी ने उनसे कहा कि जिस दिन मन लग जायेगा उसी दिन वापस बुला लेंगे।*

वास्तव में दीनदयालजी का जीवन पूर्ण रूप से संघमय था। स्वयंसेवक के गुण उनके जीवन से प्रकट होते थे। उदात्त और सहज प्रभावी। वे व्यक्ति नहीं व्यक्तित्व थे। ऐसे मानव महान महापुरुष को उनके जन्म दिवस पर कोटिशः प्रणाम। ■

(लेखक वर्तमान में सुरुचि प्रकाशन दिल्ली में सेवारत हैं)
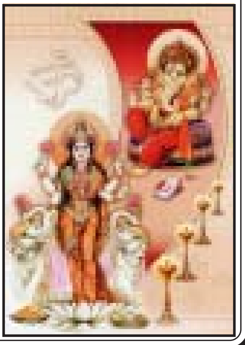
सभी सुधी पाठकों को
कमल संदेश परिवार की
ओर से 'दीपावली'
की हार्दिक शुभकामनाएं